www.hindmatamirror.com ●वर्ष: 12 ●अंक: 266 ●ठाणे, मंगलवार 30 जून, 2026 ● पेज: 8 ●मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

दैनिक ठाणे
हिंदमाता मिरर
RNI. NO. MAHHIN/2011/43060
पैनी नजर, पुख्ता खबर

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में फिट करने का वक्त आ गया है

पेज 8

मुझे थिएटर में जाकर हर तरह की फिल्में देखना पसंद है

8 पेज

सुप्रभात

झूठे से देव और मनुष्य दोनों घृणा करते हैं। झूठा अक्सर बुजदिल होता है, क्योंकि वह सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता।
- वाल्टर रेले

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (30 जून) 7:20 बजे, सूर्योदय (1 जुलाई) 6:04 बजे, **तापमान: 28 डिग्री से. (गरज के साथ बौछार।)**

शॉर्ट स्टोरी

जलाशयों में 7% से भी कम जलभंडार

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

मानसून में देरी और अब तक कम बारिश होने के कारण मुंबई को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। महानगर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले सात जलाशयों में पानी कुल भंडारण क्षमता का 7% से भी कम रह गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह छह बजे तक इन सातों जलाशयों में कुल 1,00,279 मिलियन लीटर पानी मौजूद था, जो उनकी कुल भंडारण क्षमता का केवल 6.93% है। इसके विपरीत, पिछले वर्ष इसी अवधि में इन जलाशयों में कुल क्षमता का 39.5% यानी 5,71,670 मिलियन लीटर पानी था।

आरटीई आवेदन शुल्क में 600 गुना बढ़ोतरी

हिंदमाता नेटवर्क @ नागपुर

प्रशासकीय कार्यप्रणाली को उजागर करने के लिए आरटीआई को आम जनता का कानूनी हथियार माना जा रहा है किंतु अब सरकार की ओर से इसे महंगा कर दिया गया है। पहले किसी मामले को लेकर मांगी गई जानकारी के अनुसार प्रत्येक जेराक्स कॉपी के लिए 2 रुपए का भुगतान करना होता था, किंतु अब प्रत्येक जेराक्स कॉपी के लिए 5 रुपए का भुगतान करना होगा। इसी तरह पहले सूचना के अधिकार के आवेदन के साथ केवल 5 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगता था। इसे अब 600 गुना बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया है। आरटीआई कार्यकताओं के अनुसार सरकार की यह पहल एक तरह से आरटीआई को कम करना है।

घरों से निकला 50 टन पुराना सोना!

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

सोने की कीमतों में आए दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिलता रहता है। अब सोने की कीमतें हाल ही में रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने के बाद कुछ गिरावट दिखा रही हैं। ऐसे में अब कई लोग अपनी ज्वेलरी को बेचने में लगे हैं, ताकि उससे मुनाफा कमा सके। जानकारी के मुताबिक, अप्रैल से जून तिमाही में भारतीय परिवारों ने करीब 50 टन पुराना सोना बाजार में बेचा है। इसकी बड़ी वजह मुनाफा कमाने का मौका और फ्यूचर में कीमतें गिरने का डर बताया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि आगे सोने में गिरावट आ सकती है। मार्केट में अनुमान लगाया जा रहा है कि कीमतें घटकर लगभग 1.2 लाख प्रति 10 ग्राम तक आ सकती हैं।

अटल सेतु पर अब तक 12 लोगों की मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र विधान परिषद में सोमवार को एक मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु से कूदकर आत्महत्या या इसका प्रयास करने के 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि इन 12 मृतकों में से चार लोगों के शव अब तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। मंत्री ने बताया कि 2024 में अटल सेतु से छलांग लगाने की छह घटनाएं सामने आईं। इनमें चार लोगों की मौत हुई, जिनमें से दो के शव नहीं मिल पाए जबकि दो अन्य लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया।

बच्ची से रेप और मर्डर का दोषी पाया गया भीमराव कांबले

नसरापुर के नराधम को फांसी

● पॉक्सो एक्ट के तहत 55 दिन में आया यह ऐतिहासिक फैसला

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

महाराष्ट्र के नसरापुर में 4 साल की बच्ची का रेप और मर्डर केस में पुणे की स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने आरोपी भीमराव कांबले को मौत की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत चले इस मुकदमे में 55 दिन बाद अदालत का फैसला आया है। भोर तहसील में चार साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या के इस मामले में 65 साल के भीमराव कांबले को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका था और कोर्ट को उम्रकैद या मौत की सजा में से किसी एक पर फैसला करना था। सरकारी वकील अजय मिसर ने बताया कि बच्ची के साथ करीब 39 मिनट तक लगातार अत्याचार किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 18 चोटों के निशान मिले थे। उसके साथ रेप के अलावा और भी तरह से शारीरिक शोषण किया गया था। आरोपी का डीएनए भी बच्ची के शरीर पर मिला था। कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए जांच और मेडिकल सबूतों को आधार बनाया गया। इस मामले में कुल 82 गवाहों ने अपनी गवाही दी थी। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि आरोपी पहले भी कई बार इस तरह के अपराध कर चुका है, इसलिए उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया था। उसका कहना था कि बच्ची को दिखाते समय वो खुद गिर गया था, जिससे बच्ची को चोट लगी, लेकिन सबूतों ने उसके इस दावे को झूठा साबित कर दिया। दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने सजा पर फैसला लेने के लिए अलग से सुनवाई की। इस दौरान बच्ची के पिता ने भी कोर्ट से सख्त सजा देने की मांग की थी. आखिरकार कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा देने का फैसला सुनाया है।

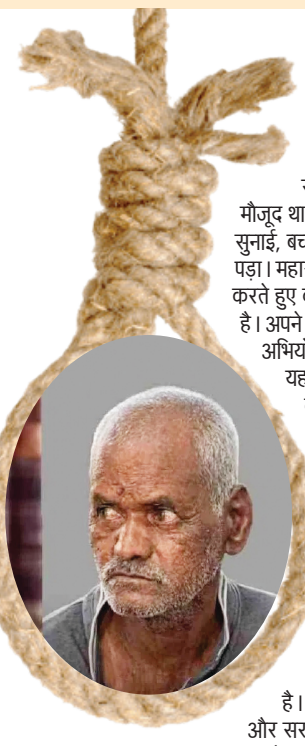

ऐसे अपराध हर बार समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं

बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और उसके द्वारा अपराध से इनकार किए जाने को सजा में रियायत देने का आधार बताया। हालांकि, अदालत ने माना कि इस मामले में आरोपी की उम्र उसके पक्ष में नहीं, बल्कि उसके खिलाफ जाती है। न्यायाधीश ने कहा, इतनी उम्र में भी आरोपी की वासना कम नहीं हुई, बल्कि और खतरनाक रूप ले चुकी है। तीन साल की मासूम बच्ची के शरीर पर मिले चोट के निशान बताते हैं कि उसके साथ कितनी बेरहमी और अमानवीयता बरती गई। आरोपी ने बच्ची के साथ जो कुछ भी किया, वह बिना किसी डर और पूरी निर्ममता से किया। उसे शायद यह भरोसा था कि पहले की तरह इस बार भी मुकदमा चलने के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि निर्भया कांड के बाद बच्चों के खिलाफ अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए कड़े कानून बनाए गए और विशेष अदालतें गठित की गईं। इसके बावजूद ऐसे जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं और ऐसे अपराध हर बार समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं।

सीएम ने किया फैसले का स्वागत

अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एस. आर. सालुंखे ने इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' करार देते हुए भीमराव कांबले को सजा सुनाई जो उस समय कठघरे में मौजूद था। जैसे ही न्यायाधीश ने मौत की सजा सुनाई, बच्ची का परिवार अदालत कक्ष में रो पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए न्यायाधीश सालुंखे ने कहा कि अभियोजन के पक्ष में काफी मजबूत साक्ष्य मिले हैं। अदालत ने टिप्पणी की, यह अपराध एक ऐसे आरोपी द्वारा हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने से संबंधित है, जिसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और गंभीर हमलों का एक लंबा इतिहास रहा है।

दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय- एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन, न्यायालय और सरकारी वकीलों ने सामूहिक प्रयासों से कार्य किया है। पूरे प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए बेहद कम समय में दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय है। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे फांसी ही होनी चाहिए।

नसरापुर मामले की टाइमलाइन

1 मई, 2026 - अपराध की सूचना और आरोपी की गिरफ्तारी
नसरापुर गांव में अपनी दादी के घर के बाहर खेल रही चार साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। एक गौशाला में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

2-3 मई, 2026 - लोगों का गुस्सा और एसआईटी का गठन
इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें नवाले ब्रिज के पास हाईवे जाम करना भी शामिल था। पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस सुरक्षा में किया गया। जांच में तेजी लाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई।

4-10 मई, 2026 - राजनीतिक प्रतिक्रिया और परिवार की अपील
राजनीतिक नेताओं ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जबकि पिता ने न्याय मिलने तक निजता बनाए रखने की सार्वजनिक अपील की। राज्य सरकार ने फास्ट-ट्रैक जांच और मुकदमा चलाने का भरोसा दिया।

16 मई, 2026 - चार्जशीट दाखिल
पुलिस ने 15 दिनों के भीतर 1,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें फोरेंसिक और डीएनए सबूत शामिल थे।

28 मई, 2026 - आरोप तय, फास्ट-ट्रैक ट्रायल शुरू
अदालत ने पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए और रोजाना इन-कैमरा सुनवाई का आदेश दिया।

21 जून, 2026 - आखिरी बहस पूरी
55 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों ने अपनी अंतिम बहस पूरी की। अभियोजन पक्ष ने मौत की सजा की मांग की।

25 जून, 2026 - दोषी करार दिया गया
अदालत ने भीमराव कांबले को अपहरण, बलात्कार और हत्या का दोषी पाया और सबूतों की अटूट कड़ी का जिक्र किया।

29 जून, 2026 - मौत की सजा
अदालत ने कांबले को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।

महाराष्ट्र के सबसे तेजी से पूरे हुए मुकदमों से एक बना ये केस

इस मामले का जिक्र अक्सर महाराष्ट्र के हालिया कानूनी इतिहास में सबसे तेजी से पूरे हुए मुकदमों में से एक के तौर पर किया जा रहा है। इसकी वजह थी पुलिस की तेज कार्रवाई, 1200 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट और स्पेशल जज एस.आर. सालुंखे के सामने रोजाना होने वाली इन-कैमरा सुनवाई।

तेज कानूनी प्रक्रिया ने खींचा ध्यान

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजय मिसर ने यह तर्क देते हुए मौत की सजा पर जोर दिया कि अपराध की क्रूरता सुप्रीम कोर्ट के रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत को पूरा करती है, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र और गुनाह से इनकार को कम करने वाले फैक्टर बताया। फैसले का दौर तब आया जब कोर्ट ने कई गवाहों की गवाही रिकॉर्ड की और बड़े पैमाने पर फोरेंसिक और हालात के सबूतों की जांच की, जिसके कारण 25 जून को सजा हुई।

महाराष्ट्र टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग

भुसे के इस्तीफे की मांग

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। विधान परिषद में भुसे ने कहा कि इस मामले में दिन में बाद में वह सदन में विस्तृत वक्तव्य देंगे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का पहले ही गठन किया जा चुका है तथा चार से अधिक जांच दल भी बनाए गए हैं और जांच जारी है। भुसे ने कहा कि इस मामले में सरकार का रुख कड़ी कार्रवाई करने का है। उन्होंने कहा कि साथ ही भविष्य में परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ कैसे करानी हैं, इस संबंध में भी निर्णय लिए जाएंगे।

दानवे ने उठाया मुद्दा

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सदस्य अंबादास दानवे ने सदन में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि जब सरकार के सामने हाल में नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक का उदाहरण था, तो टीईटी और अन्य परीक्षाओं के लिए एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की अनियमितताएं हो रही हैं और प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दानवे ने कहा, यदि सरकार परीक्षाएं सही ढंग से नहीं करा सकती, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

आरोपियों पर मकोका लगाने पर विचार

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिए गए उनके इस बयान के बीच विपक्ष पिछले सप्ताह हुए टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर भुसे के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

समस्तीपुर का बिजेंद्र गुप्ता मामले का मास्टरमाइंड

टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी बिजेंद्र गुप्ता को पुलिस ने दबोच लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद परीक्षा घपले के तार कई राज्यों से जुड़ते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पेपर लीक मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, एक कथित देशव्यापी सिंडिकेट की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि इस पूरे नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला ब्रजेंद्र गुप्ता है। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि ब्रजेंद्र की भूमिका सिर्फ इसी मामले तक सीमित नहीं है; वह कई राज्यों में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वाले नेटवर्क से सालों से जुड़ा रहा है। पेपर लीक मामले में ब्रजेंद्र गुप्ता का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 2011 में सामने आए एक बड़े पेपर लीक मामले में भी आरोपी है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला बिजेंद्र गुप्ता न सिर्फ महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक में शामिल था। पुलिस का कहना है कि अब तक महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में पकड़े गए 3 आरोपी उसके इशारों पर काम कर रहे थे। बिजेंद्र गुप्ता पिछले 25 साल से पेपर लीक रैकेट चला रहा है। उसके तार कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं से जुड़े हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए बिहार, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में तफ्तीश कर रही है।

त्रुटिरहित परीक्षाएं आयोजित कराना सरकार की जिम्मेदारी

● कांग्रेस सदस्य सतेज पाटील ने कहा कि त्रुटिरहित तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के जयंत असगांवकर ने कहा, इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।

● उनकी पार्टी के सदस्य धीरज लिंगाडे ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के सदस्य अरुण लाड ने कहा कि राज्य में प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए कानून पर्याप्त रूप से सख्त नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं।

● उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में टीईटी-2026 परीक्षा गत रविवार को आयोजित होनी थी, लेकिन एक दिन पहले शनिवार को ठाणे जिले की पुलिस को प्रश्नपत्र के लीक होने का पता चलने पर तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई और परीक्षा स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच के लिए ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाबराव उगले की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है।

पेपर लीक का केंद्र बन गया है महाराष्ट्र : शिवसेना (यूबीटी)

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को भिवंडी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सड़ चुकी है और इतने जघन्य अपराधों के बावजूद किसी को भी कोई सजा नहीं मिलती। यही कारण है कि प्रश्नपत्र लीक का धंधा खुलेआम फल-फूल रहा है।

महाराष्ट्र में अगले साल से ऑनलाइन होगी टीईटी की परीक्षा

महाराष्ट्र विधानसभा में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पेपर लीक पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक के बाद अब अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन करने की तैयारी है। सरकार इस प्लानिंग के लिए एक कमेटी का गठन करेगी। वहीं, टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले पर शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने सरकार की ओर से निवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभ्यर्थियों से पुनर्परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

किसानों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने पर महाराष्ट्र सरकार का जोर

अवैध साहूकारी पर लगेगी लगाम

● दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा, सरकार तैयार कर रही नई कानून-व्यवस्था

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध साहूकारी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कानून को और सख्त बनाने का फैसला किया है। सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील ने विधानसभा में कहा कि नए कानून में मौजूदा प्रावधानों की तुलना में अधिक कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा, ताकि अवैध साहूकारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। मंत्री बाबासाहेब पाटील ने कहा कि सरकार किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराने, अवैध साहूकारी पर सख्त नियंत्रण रखने और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र किसान ऋण से वंचित नहीं रहेगा। जिन किसानों को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के बकाया ऋण के कारण नया फसल ऋण नहीं मिल पा रहा है, उन्हें राष्ट्रीयकृत और अन्य पात्र बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से अब तक साहूकारों ने 400 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है जबकि बैंकों ने 12,111 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं। इस बीच विपक्षी दलों ने किसानों को बिना शर्त ऋण माफी देने की मांग की है।

अमरावती में कार्रवाई के आंकड़े

मंत्री ने बताया कि अमरावती जिले में अवैध साहूकारी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई जारी है। अब तक प्राप्त 343 शिकायतों में से 266 मामलों की जांच पूरी की जा चुकी है। इनमें 34 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और 48 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र साहूकारी कानून के तहत जिला उपनिबंधक कार्यालय को मिली 54 शिकायतों में से 44 मामलों का निपटारा कर किसानों को राहत देने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत

सरकार ने अवैध साहूकारी रोकने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर त्रिसदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया है। साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला समन्वय समिति फसल ऋण स्वीकृति और वितरण की नियमित निगरानी कर रही है तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। विधानसभा में इस विषय पर सदस्य सुलभा खोडके के प्रश्न पर कई सदस्यों ने भी पूरक प्रश्न उठाए।

महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी अनिवार्य

नियमों का उल्लंघन करने पर रद्द हो सकती है मान्यता: मंत्री

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे ने सोमवार को कहा कि राज्यभर के सभी माध्यमों के स्कूलों में मराठी भाषा की पढ़ाई और इस विषय की परीक्षा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र में सभी माध्यमों के स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान महाराष्ट्र राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा का अनिवार्य शिक्षण एवं अध्ययन अधिनियम, 2020 के तहत किया गया है।

स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है

मंत्री ने कहा, यदि कोई स्कूल प्रावधानों को लागू नहीं करता है तो पहले उसे उल्लंघन सुधारने के लिए कहा जाएगा। यदि इसके बाद भी वह मराठी नहीं पढ़ाता है तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

हिंदमाता एंकर: केतन अग्रवाल मर्डर केस में बड़ा अपडेट, कोर्ट ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई

सिया गोयल को लेकर नए खुलासे, केतन से एक करोड़ रुपए लेकर चेतन को दिए

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

पुणे के 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुणे की अदालत ने मर्डर केस के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दोनों की पुलिस हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है। पुणे के हाईप्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि केतन की हत्या की आरोपी उसकी मंगेतर सिया ने हत्या से पहले केतन से 1 करोड़ रुपए लेकर अपने प्रेमी चेतन को दिए थे। यह रकम शादी की शॉपिंग के नाम पर ऐंठी गई थी। आरोप है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन हत्याकांड को अंजाम दिया। 18 जून को दोनों ने मिलकर केतन को लोहागढ़ किले से नीचे खाई में धकेल दिया था।

केतन से ऐंठी गई एक करोड़ की रकम

पुलिस की जांच में सामने आया है कि सिया ने शादी की तैयारियों के नाम पर केतन से 1 करोड़ की रकम मांगी थी। जिसे उसने अपने प्रेमी चेतन को करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दिए थे। बता दें चौधरी आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से था, इसलिए उसने गोयल से कहा था कि उसे स्टेबल होने में कम से कम तीन साल लगेंगे।

तीन साल बाद शादी करने का प्लान

चेतन और सिया के बीच कथित तौर पर यह तय हुआ था कि केतन की हत्या के बाद, शक से बचने के लिए वह तीन साल तक शादी नहीं करेगी। जब चौधरी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते और मामला लोगों की नजर से हट जाता, तब वे शादी करने वाले थे। जांचकर्ताओं का कहना है कि यह टाइमलाइन जांच से बचने और आखिरकार गोयल के परिवार की मंजूरी पाने की प्लानिंग का हिस्सा थी।

भाई ने जबरन कैब में बिठाया

इस मामले में कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने भी खुलासा किया है। जाधव वहीं कैब ड्राइवर जिसकी कैब से सिया प्री वेडिंग शूट के लिए मुंबई एयरपोर्ट गई थी। जाधव ने बताया कि प्री वेडिंग शूट के लिए बाली दौरे की लिए रवाना होने से पहले सिया का व्यवहार सामान्य नहीं था, वह कार में बैठने तक से इनकार कर रही थी, तभी उसके भाई ने उसे जबरन कैब में बिठाया था। बाद में सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा लिया जिसके बाद बाली दौरा कैंसिल करना पड़ा था।

क्या था हत्या का प्लान?

पुलिस के अनुसार, केतन की हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी। इसमें यह भी शामिल था कि किले से धक्का देते समय सिया केतन की पहुंच से दूर रहे। इसके लिए दोनों ने प्लान किया था कि ऐसी स्थिति मर वे एक-दूसरे को सिग्नल देंगे। एक अधिकारी ने बताया कि प्लान के मुताबिक, सिया को नीचे बैठकर सिग्नल देना था, जिसके बाद चौधरी को ऊपर आना था और अग्रवाल को धक्का देना था। दोनों ने तय किया था कि वह या तो पानी पीने के बहाने या जूते के फीते बांधने के बहाने नीचे बैठेंगी। अधिकारी ने कहा कि नीचे बैठना ही सिग्नल था। हालांकि, यह गोयल को सुरक्षित रखने के लिए भी एक सोच-समझकर उठाया गया कदम था।

कार के बजाय स्कूटर से लोहागढ़ किले तक का सफर

सिग्नल जानबूझकर ऐसा चुना गया था ताकि धक्का देते समय गोयल पीड़ित की पहुंच में न हों। उन्हें डर था कि अगर चेतन केतन को धक्का देता हैं और गिरते समय केतन सिया को पकड़ने की कोशिश करता हैं, तो वह भी खाई में गिर सकती हैं। 18 जून को सिया और केतन का पीछा करते समय चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने का भी पूरा ध्यान रखा था। जान बूझकर कार के बजाय स्कूटर से लोहागढ़ किले तक का 90 किमी का सफर किया।

'कमीशन' पर बातचीत वाला वीडियो एआई से बनाया गया, आवाज भी डब की गई : शिवसेना विधायक

हिंदमाता नेटवर्क @ कोल्हापुर

शिवसेना विधायक राजेश क्षीरसागर ने दावा किया है कि उन्हें एक सरकारी ठेकेदार से 'कमीशन' के भुगतान पर चर्चा करते हुए दिखाने वाला एक वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से छेड़छाड़ कर बनाया गया है और उसमें उनकी आवाज 'डब' की गयी है। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में क्षीरसागर ने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सतेज पाटिल पर निशाना साधा।

■ उन्होंने इस वीडियो की जांच के लिए साइबर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोल्हापुर जिले से विधायक क्षीरसागर ने कहा कि उनकी टीम पूरे मामले पर नजर रख रही है और कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। क्षीरसागर ने दावा किया कि यह वीडियो एआई की मदद से तैयार किया गया है और इसमें मेरी आवाज डब की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो उनकी राजनीतिक छवि और करियर को नुकसान पहुंचाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह वीडियो 14 जनवरी को कोल्हापुर नगर निगम चुनाव से ठीक दो दिन पहले वायरल किया गया था। उन्होंने कहा कि उन चुनावों में पहली बार महायुति ने नगर निगम में सत्ता हासिल की थी।

पुलिस निरीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही हो : राकांपा विधायक अव्हाड

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र अव्हाड ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही का नोटिस सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त पुलिस निरीक्षक का व्यवहार एक विधायक के विशेषाधिकारों में दखल देने के समान था। अव्हाड ने विधानसभा में गत सप्ताह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सदन में हुई एक बहस का जिक्र किया।

■ अव्हाड ने कहा कि उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकार मादक पदार्थ से जुड़े मामलों में पुलिस थाने के प्रभारी को जवाबदेह ठहराए और जिन पुलिस थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थ बरामद किये जाएं, वहां के निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी एक सामान्य नीतिगत सुझाव था और किसी अधिकारी को लक्षित नहीं था। अव्हाड ने आगे कहा कि हालांकि, उनके भाषण के बाद उन्हें ऐसा पेश करने की कोशिश की गई कि उन्होंने ठाणे ज़िले में अपने निर्वाचन क्षेत्र, मुंब्रा-कलवा को बदनाम किया है।

■ राकांपा (शप) नेता ने दावा किया कि मुंब्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे ने ऐसा व्यवहार किया जैसे विशेष रूप से उन्हें राजनीतिक निशाना बनाने की कोशिश की गई। अव्हाड ने आरोप लगाया कि ऐसा माहौल लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि विधायकों को बिना किसी बदले की कार्रवाई के डर के कानून-व्यवस्था और मादक पदार्थ की समस्या से जुड़े मुद्दे उठाने की आजादी होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि वह नोटिस पर विचार करेंगे और तय करेंगे कि मौजूदा मॉनसून सत्र के खत्म होने से पहले इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए या नहीं।

दोहरे ऑटो परमिट पर सवाल

आरटीओ ने पुलिस को कार्रवाई की संस्तुति भेजी

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

ठाणे और बोरीवली क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की जांच में एक ही महिला, श्रीमती शोभा रामनाथ हुलमुख, के नाम पर दो अलग-अलग ऑटो रिक्शा परमिट दर्ज पाए जाने का मामला सामने आया है। जांच में एमएच-47-डी-4629 (बोरीवली) और एमएच-04-एचजे-5056 (ठाणे) नंबर के ऑटो रिक्शा के परमिट एक ही नाम पर दर्ज मिले हैं। प्रारंभिक जांच में शासन के समक्ष कथित रूप से गलत या भ्रामक जानकारी देकर परमिट प्राप्त किए जाने की आशंका जताई गई है।

कार्रवाई की सिफारिश

उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर ने 10 जून 2026 को वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन को पत्र भेजकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की अनुशंसा की। महाराष्ट्र में सामान्यतः एक पात्र व्यक्ति को एक ही ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जाने का प्रावधान है, ऐसे में यह मामला नियमों के संभावित उल्लंघन की ओर संकेत करता है।

एफआईआर का इंतजार

आरटीओ की लिखित संस्तुति के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से पुलिस की कार्रवाई और जांच की गति पर सवाल उठ रहे हैं। नागरिकों और रिक्शा चालक संगठनों ने मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी या शासन को गुमराह करने के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस मामले में पुलिस और परिवहन विभाग की अगली कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

राज्य मंत्री भागवत मकवाना का भव्य स्वागत

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर

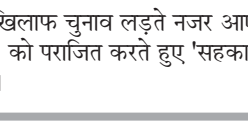

उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री भागवत प्रसाद मकवाना के उल्हासनगर आगमन पर महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के पूर्व कार्याध्यक्ष एवं शिवसेना के वरिष्ठ नेता महेश सुखरामनी तथा राधाचरण कारोटिया के नेतृत्व में उनका पुष्पगुच्छ और शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। फरवर लाइन स्थित गोगा मंदिर प्रांगण में आयोजित स्वागत समारोह में विकास, सामाजिक समरसता, स्वच्छता, सफाई कर्मचारियों के कल्याण तथा जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान भागवत प्रसाद मकवाना ने संबंधित विषयों पर सकारात्मक पहल करते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। समारोह में पूर्व महापौर मालती कारोटिया, राधाचरण कारोटिया, रॉकी कारोटिया, राजेश राजवड़िया, कन्हैया कारोटिया, नरेंद्र एवं सुनील कारोटिया, एडवोकेट विनोद उज्जैनवाल, रामवीर कारोटिया सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

ठाणेवासियों के लिए 24 घंटे जलापूर्ति बंद

● स्टेम प्राधिकरण के शटडाउन के चलते चरणबद्ध तरीके से होगी पानी की सप्लाई

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

ठाणेवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। संभावित जल संकट को ध्यान में रखते हुए स्टेम प्राधिकरण ने ठाणे महानगरपालिका को होने वाली जलापूर्ति 24 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। यह शटडाउन बुधवार 1 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से गुरुवार 2 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में स्टेम प्राधिकरण से शहर को पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी।

चरणबद्ध तरीके से होगी आपूर्ति

हालांकि, ठाणे महानगरपालिका ने अपनी जलापूर्ति योजना के माध्यम से शहर में चरणबद्ध तरीके से एक समय पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसके तहत घोड़बंदर रोड, पातलीपाड़ा, पवार नगर, कोठारी कंपाउंड, आजाद नगर, डोंगरीपाड़ा, वाघबीळ, आनंद नगर, कासारवडवली, ओवला, रेतीबंदर तथा मुंब्रा के कुछ हिस्सों में बुधवार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक जलापूर्ति बंद रहेगी। वहीं समतानगर, ऋतुपार्क, सिद्धेश्वर, इटरनिटी, जॉनसन, जेल परिसर, साकेत, उथलसर, रुस्तमजी, दोस्ती, आकृति तथा वर्तक नगर (म्हाडा) सहित अन्य क्षेत्रों में बुधवार रात 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी।

कम दबाव से मिल सकता है पानी

महानगरपालिका ने बताया कि शटडाउन समाप्त होने के बाद भी अगले एक से दो दिनों तक कम दबाव से जलापूर्ति होने की संभावना है। प्रशासन ने नागरिकों से पहले से आवश्यक मात्रा में पानी का संग्रह करने, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने तथा इस दौरान महानगरपालिका का सहयोग करने की अपील की है।

कॉलेज में छात्र की मौत

छात्र को परिसर में आया हार्ट अटैक

हिंदमाता संवाददाता @ नवी मुंबई

नवी मुंबई के कोपरखैरणे सेक्टर-5 स्थित विवेकानंद महाविद्यालय में एक 17 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर हृदयाघात से मौत हो गई। इतनी कम उम्र में छात्र की मौत से कॉलेज परिसर और क्षेत्र में शोक तथा आश्चर्य का माहौल है। मृत छात्र की पहचान शिव पाल के रूप में हुई है, जो पावना का निवासी था और बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत था।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही गई जान

जानकारी के अनुसार, शिव पाल रोज की तरह बुधवार सुबह कॉलेज पहुंचा था। सुबह करीब साढ़े सात बजे कॉलेज के भूतल पर उसे अचानक सीने में तकलीफ हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद कॉलेज के छात्र और कर्मचारियों ने उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से छात्रों और शिक्षकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

पंढरपुर और मिरज जाने वाले आषाढ़ी यात्रा के लिए 54 विशेष ट्रेनें

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मध्य रेल की विशेष व्यवस्था

हिंदमाता नेटवर्क @ पंढरपुर

आषाढ़ी यात्रा के अवसर पर श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए मध्य रेल ने 22 से 29 जुलाई 2026 के बीच पंढरपुर और मिरज के लिए कुल 54 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन आरक्षित और अनारक्षित दोनों श्रेणियों में किया जाएगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके।

कई शहरों को मिलेगा लाभ

मध्य रेल के अनुसार नागपुर-मिरज, नवीन अमरावती-पंढरपुर, खामगांव-पंढरपुर तथा लातूर-पंढरपुर के बीच कुल 20 आरक्षित विशेष सेवाएं चलाई जाएंगी। वहीं भुसावल-पंढरपुर, कोल्हापुर-कुर्डुवाड़ी और पुणे-मिरज मार्गों पर 34 अनारक्षित विशेष ट्रेनें संचालित होंगी। इन ट्रेनों का ठहराव मार्ग के प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके।

1 जुलाई से आरक्षण शुरू

गाड़ी संख्या 01205, 01206, 01119, 01120, 01121, 01122, 01101 और 01102 के लिए आरक्षण 1 जुलाई 2026 से सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगा। अनारक्षित डिब्बों के टिकट यूटीएस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होंगे। यात्री टिकट बुकिंग के लिए रेलवन (फ्रंडली) ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

जरूरत पड़ने पर और ट्रेनें

मध्य रेल ने बताया कि आषाढ़ी मेले के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने पर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की समय-सारिणी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट अथवा एनटीईएस ऐप पर देखकर ही यात्रा की योजना बनाएं।

चार प्रभागों के सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर

उल्हासनगर महानगरपालिका की चारों प्रभाग समितियों के सभापति चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच सोमवार को सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल होने के साथ ही अटकलों पर विराम लग गया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान शिवसेना (शिंदे) के कल्याण जिला प्रमुख गोपाल लांडगे की मौजूदगी से चुनावी माहौल और गर्म हो गया। चारों प्रभाग समितियों के लिए दाखिल नामांकन के अनुसार प्रभाग समिति क्रमांक-1 से भावना उलेकर, प्रभाग समिति क्रमांक-2 से संगमित्रा हजारे, प्रभाग समिति क्रमांक-3 से संगीता सकपाले तथा प्रभाग समिति क्रमांक-4 से सोहना जेसवानी ने सभापति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें दो उम्मीदवार शिवसेना (शिंदे) और दो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बताए जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब गुरुवार को होने वाले चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सत्तारूढ़ महायुति के घटक दलों के बीच सभापति पदों को लेकर कई दावेदार सामने आए थे, लेकिन नामांकन के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। अब केवल चुनावी औपचारिकता शेष है। कोकण विभाग के विभागीय आयुक्त के आदेशानुसार गुरुवार को विशेष महासभा में चारों प्रभाग समितियों के सभापति पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद यह तय होगा कि आगामी कार्यकाल में चारों प्रभाग समितियों की कमान किन जनप्रतिनिधियों के हाथों में रहेगी।

उल्हासनगर के विकास मुद्दों पर आयलानी की पैरवी

उपमुख्यमंत्रियों और राजस्व मंत्री से मुलाकात

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर

महाराष्ट्र विधानमंडल के वर्षाकालीन अधिवेशन के दौरान सोमवार को उल्हासनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुमार आयलानी ने विधानभवन में राज्य के उपमुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा ताई अजित पवार तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात कर शहर के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया गया।

सड़कों के लिए मांगी मंजूरी

विधायक आयलानी ने उल्हासनगर के प्रमुख मार्गों को सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़कों में परिवर्तित करने के लिए तैयार 99 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को तत्काल प्रशासनिक मंजूरी देने की मांग की। इसके साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मार्गों के सीसी निर्माण हेतु 110 करोड़ रुपए का नया प्रस्ताव तैयार कर उसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह भी सरकार से किया।

मेट्रो और पानी पर जोर

बैठक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मेट्रो-5अ (दुगार्डी-उल्हासनगर) परियोजना का कार्य जल्द शुरू कर उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की मांग भी उठाई गई। आयलानी ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से शहर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को आधुनिक एवं सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने उल्हासनगर महानगरपालिका की स्वतंत्र जलापूर्ति योजना को तत्काल मंजूरी देकर आवश्यक निधि उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि शहर की पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

आरुष अस्पताल मामले में एसआईटी जांच की मांग

पुलिस जांच पर उठे सवाल, डीजीपी को भेजी शिकायत

हिंदमाता संवाददाता @ नालासोपारा

विरार स्थित आरुष अस्पताल में 16 वर्षीय अदिति दुबे की कथित चिकित्सकीय लापरवाही से हुई संदिग्ध मौत के मामले में दीनदयाल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पांडे ने महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को विस्तृत शिकायत भेजकर जांच स्थानीय विरार पुलिस से हटाकर विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

एफआईआर में देरी पर सवाल

शिकायत में कहा गया है कि घटना 10 अक्टूबर 2025 की है, जबकि एफआईआर 21 मई 2026 को दर्ज की गई। हेमंत पांडे का आरोप है कि करीब सात महीने की देरी से प्राथमिकी दर्ज होने से जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और इस दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

नाम हटाने का आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रारंभिक शिकायत में डॉ. प्रमोद यादव, डॉ. अभिनत परदेशी और डॉ. कोठारी के नाम शामिल थे, लेकिन एफआईआर दर्ज करते समय अस्पताल संचालक डॉ. प्रमोद यादव का नाम हटा दिया गया। उनका दावा है कि सिविल सर्जन की रिपोर्ट में अस्पताल संचालक की प्रथम दृष्टया लापरवाही का उल्लेख है।

निष्पक्ष जांच की मांग

हेमंत पांडे ने यह भी आरोप लगाया कि भर्ती से लेकर रेफर करने तक की पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव में काम करने का आरोप लगाते हुए डीजीपी से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में एसआईटी गठित कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

मुंब्रा के चार लापता बच्चे लखनऊ से बरामद

हिंदमाता संवाददाता @ मुंब्रा

मुंब्रा से लापता हुए चार नाबालिग बच्चों को मुंब्रा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में बच्चों के साथ मौजूद 20 वर्षीय युवक मोहम्मद कैफ अब्दुल कयूम खान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे के अनुसार, 25 जून को 15 से 17 वर्ष आयु की तीन लड़कियां और 13 वर्षीय एक लड़का क्लास जाने के लिए घर से निकले थे। उन्होंने परिजनों से दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर लौटने की बात कही थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं आए। इसके बाद 26 जून को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मुंब्रा, कल्याण, ठाणे, कुर्ला और घाटकोपर रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान एक बच्चे का मोबाइल फोन सक्रिय होने पर उसकी लोकेशन लखनऊ मिली। पुलिस टीम ने लखनऊ के मंडी क्षेत्र से चारों बच्चों को बरामद कर लिया। पुलिस का दावा है कि मोहम्मद कैफ बच्चों को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया था।

शॉर्ट स्टोरी

शिक्षा के लिए करोड़ों का सहयोग

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

राजपुरोहित समृद्धि फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'नववेतना संवाद' में शिक्षा के क्षेत्र में समाज की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी भामाशाहों ने बालिका शिक्षा और छात्रावास निर्माण के लिए करोड़ों रुपए के सहयोग की घोषणा की। मुख्य अतिथि विधायक छगनसिंह राजपुरोहित ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। उन्होंने शिक्षा के लिए सहयोग देने वाले दानदाताओं का आभार व्यक्त किया। फाउंडेशन के संस्थापक प्रतापराज जैतपुरा ने बताया कि जयपुर में समाज की बेटियों के लिए छात्रावास खरीदा जा चुका है, जबकि अध्यक्ष अर्जुन सिंह तिवरी ने कोटा में छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का लक्ष्य घोषित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक दान देकर करोड़ों रुपए जुटाए। कार्यक्रम में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों ने शिक्षा, संस्कार और सामाजिक एकता पर विचार रखे। अध्यक्षता समाजसेवी मनोजभाई दासपा ने की, जबकि अंत में गणपत सिंह पांचडोलिया ने आभार व्यक्त किया।

कॉमनवेल्थ के लिए दो खिलाड़ी चयनित

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मध्य रेल के लिए गर्व की बात है कि उसके दो एथलीटों का चयन कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह प्रतियोगिता 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होगी। चयनित खिलाड़ियों में तेजस शिर्से (110 मीटर हर्डल्स) और समरदीप सिंह गिल (शॉट पुट) शामिल हैं। दोनों खिलाड़ी मुंबई मंडल से जुड़े हैं। तेजस शिर्से मध्य रेल में वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट परीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, जबकि समरदीप सिंह गिल वरिष्ठ लिपिक हैं। दोनों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारतीय रेल और मध्य रेल का नाम रोशन किया है। उनका चयन उनकी मेहनत और मध्य रेल खेल संघ (सीआरएसए) द्वारा उपलब्ध कराई गई बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं का परिणाम माना जा रहा है। मध्य रेल खेल संघ खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, विशेषज्ञ कोचिंग, प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अवसर और नौकरी के साथ खेल में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराता रहा है। मध्य रेल ने दोनों खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ को बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि वे कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश और रेलवे का गौरव बढ़ाएंगे।

नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस समिति ने सोमवार को घाटकोपर (पूर्व) स्थित बाल्कनजी बारी हॉल में पत्रकार परिषद आयोजित कर नीट-2026 प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस अध्यक्ष केतन शाह के नेतृत्व में किया गया। पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है और लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्षों में कई परीक्षा पत्र लीक हुए हैं तथा दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सप्रा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की जगह पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी।

300 विद्यार्थियों को मिली मुफ्त कॉपियां

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस एवं हिंदू हृदयसम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शिवसेना शहर जिला शाखा द्वारा जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कॉपी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 300 स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त कॉपियां वितरित की गईं। कार्यक्रम में जिला सह-संपर्क प्रमुख मनोज गगे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन का नेतृत्व पूर्व शहर प्रमुख मोहन वल्लाल, पूर्व महानगर प्रमुख अरुण पाटील, पूर्व जिला संघटिका वैशाली मेस्त्री, उपशहर प्रमुख गणेश मोरे एवं पश्चिम सचिव नितेश दांडेकर ने किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, अनुशासन और मेहनत के बल पर उज्ज्वल भविष्य बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिवसेना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

भिवंडी निजामपुर नगर निगम मुख्यालय के बाहर सोमवार से अपंग विकास महासंघ के नेतृत्व में दिव्यांग नागरिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार, 17 अप्रैल को नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था और 18 मई को अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन किसी भी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में नगर निगम के बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा दिव्यांग कल्याण के लिए आरक्षित करना, दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता, लाइसेंसधारी स्टॉलों का आवंटन तथा कॉम्प्लेक्स और मॉल में पांच प्रतिशत दुकानें आरक्षित करना शामिल है। इसके अलावा विवाह सहायता, दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अनुदान, आवास योजना, निःशुल्क कृत्रिम अंग और परामर्श केंद्र की भी मांग की गई है। अब इस आंदोलन और नगर निगम की आगामी कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

रंगायतन की देरी पर सांसद सख्त

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी

भिवंडी शहर के एकमात्र सांस्कृतिक केंद्र स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रंगायतन की मरम्मत में हो रही लगातार देरी पर भिवंडी के सांसद सुरेश म्हात्रे (बाल्या मामा) ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। रंगायतन का निरीक्षण करने पहुंचे सांसद ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम अधिकारियों से कहा कि यदि ठेकेदार निर्धारित समय में कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उसका ठेका तत्काल निरस्त किया जाए। उन्होंने ठेकेदार को अंतिम चार माह की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि इसके बाद भी काम पूरा नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान महापौर नारायण चौधरी, मनपा अधिकारी और संबंधित ठेकेदार मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि वर्ष 2017 से जर्जर हालत के कारण बंद पड़े रंगायतन के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन धनराशि में देरी और निर्माण कार्य की सुस्ती के कारण परियोजना अब तक अधूरी है। मनपा ने वर्ष 2023 में मरम्मत का ठेका दिया था, जिसे तीन बार समय-विस्तार मिलने के बावजूद कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया है। सांसद ने कहा कि नौ वर्षों से रंगायतन बंद रहने से विद्यार्थियों, कलाकारों और रंगकर्मियों को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हिंदमाता एंकरः परिवर्तन पैनल को मिली हार, सहकार पैनल ने बनाई बढ़त

बैंक चुनाव में शिंदे-चव्हाण की रणनीति सफल, सहकार पैनल की जीत

हिंदमाता संवाददाता @ ठाणे

ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के पैनल प्रणाली से संपन्न हुए चुनाव में केंद्र और राज्य में सत्ता में सहयोगी दल होने के बावजूद भाजपा और शिवसेना के उम्मीदवार ही एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए। आखिरकार इस चुनाव में 'परिवर्तन पैनल' को पराजित करते हुए 'सहकार पैनल' ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया।

रणनीति से साधा चुनावी समीकरण

दरअसल, ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक पर पिछले कई वर्षों से हितेंद्र ठाकूर के नेतृत्व वाली बहुजन विकास आघाड़ी का दबदबा रहा है। इस बार बैंक की सत्ता अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और रवींद्र चव्हाण ने इस चुनाव में राजनीतिक चाणक्यनीति का सहारा लिया। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में सहकार पैनल के माध्यम से शिंदे गुट के कुछ उम्मीदवारों के साथ विधायक किसन कथोरे के नेतृत्व में भाजपा के भी कई उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं उनके मुकाबले 'परिवर्तन पैनल' में भी भाजपा के चार और शिंदे गुट के तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। दोनों पैनलों में अपने-अपने उम्मीदवार उतारने के पीछे दोनों नेताओं ने यह तर्क दिया था कि उनके पास उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है।

परिणामों ने बदला समीकरण

हाल ही में घोषित चुनाव परिणामों में भाजपा के 8 और शिंदे गुट के 5 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। कुल 21 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में बहुमत के लिए 11 सीटों की आवश्यकता थी, जबकि महायुति के कुल 13 उम्मीदवार जीतकर आए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एकनाथ शिंदे और रविंद्र चव्हाण की राजनीतिक चाणक्यनीति सफल रही। वहीं दूसरी ओर, इस परिणाम को हितेंद्र ठाकूर की बहुजन विकास आघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

अब सत्ता पर अंतिम फैसला

अब ठाणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सत्ता को लेकर अंतिम निर्णय महायुति के वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लिया जाएगा, ऐसी राजनीतिक चर्चा चल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बैंक की सत्ता की बागडोर महायुति अपने पास रखती है या फिर उसे बहुजन विकास आघाड़ी को सौंपती है।

दंपती को भारी पड़ा मटन के बाद दही खाना

• पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक

हिंदमाता नेटवर्क @ नाशिक

नाशिक जिले से एक ऐसी हृदयविदारक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अक्सर हम स्वाद के चक्कर में भोजन के नियमों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन कभी-कभी यह छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पहले तरबूज खाने से एक ही परिवार के लोगों की मौत, फिर आमरस खाने से फूड पॉइजनिंग और अब नाशिक की बागलान तहसील के आखतवाड़े गांव में एक बुजुर्ग किसान दंपती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां मटन और दही का सेवन उनके जीवन पर भारी पड़ गया। रविवार की रात, एक साधारण से दिखने वाले भोजन के साथ शुरू हुई यह कहानी एक बड़ी त्रासदी में बदल गई। आखतवाड़े गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने रात के भोजन में मटन का सेवन किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मटन खाने के बाद उन्होंने दही भी खाया। भोजन करने के कुछ ही समय बाद, 68 वर्षीय द्वारकाबाई शांताराम 'ालीज और उनके 78 वर्षीय पति शांताराम 'ालीज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें तीव्र बेचैनी होने लगी, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।

उपचार के दौरान पत्नी की मौत

अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन द्वारकाबाई की हालत तेजी से बिगड़ती गई। उपचार के दौरान ही द्वारकाबाई का निधन हो गया। वहीं, उनके पति शांताराम 'ालीज की हालत भी अत्यंत नाजुक बनी हुई है। उन्हें मालेगांव के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां वे फिलहाल जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी स्थिति अभी भी काफी चिंताजनक है।

मटन या दही: मौत की वजह क्या?

इस घटना ने पूरे नाशिक परिसर में सनसनी फैला दी है और लोग इस बात को लेकर तर्क-वितर्क कर रहे हैं कि आखिर फूड पॉयजनिंग की असल वजह क्या थी। क्या वह मटन खराब था, या फिर मटन के तुरंत बाद दही का सेवन करना जहर बन गया? चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि मटन और दही का एक साथ सेवन करना या भोजन का बासी होना, गंभीर फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। हालांकि, इस मामले में जहर का सटीक स्रोत अभी तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है।

पुलिस जांच और लैब रिपोर्ट का इंतजार

मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तत्काल कदम उठाए हैं। पुलिस ने घटना की सघन जांच शुरू कर दी है और सच्चाई का पता लगाने के लिए उस रात खाए गए भोजन के नमूने इकट्ठा कर लिए हैं। इन नमूनों को रासायनिक जांच के लिए पुणे की लैब में भेजा गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। आखतवाड़े गांव में इस समय मातम छाया हुआ है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि खान-पान के प्रति थोड़ी सी भी असावधानी कितने बड़े संकट को निमंत्रण दे सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि विरुद्ध आहार जैसे मांस और डेयरी उत्पादों का गलत कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को टाला जा सके।

महाराष्ट्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा

पश्चिमी तट पर समान नियम लागू करने की तैयारी

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में नौकाओं से समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया है। राज्य के मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने सोमवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक मछली पकड़ने पर रोक लगाई थी। वही अब दक्षिण-पश्चिम मानसून में देरी को देखते हुए अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है।

मछलियों के संरक्षण और मछुआरों की सुरक्षा पर जोर

सरकार के मुताबिक, इस फैसले का मकसद समुद्री मछलियों को प्रजनन के लिए पर्याप्त समय देना, मछली भंडार का संरक्षण करना और मछलियों से जुड़े संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखना है। नितेश राणे ने कहा कि मानसून के शुरूआती दौर में तेज हवाएं, चक्रवात, असमय बारिश और उफनता समुद्र मछुआरों के लिए बड़ा खतरा होता है। ऐसे में प्रतिबंध बढ़ाने से जानमाल की भी होगी।

मछुआरों ने की थी प्रतिबंध बढ़ाने की मांग

हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात के इंडियन वेस्ट कोस्ट फिशरमेन फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मत्स्य मंत्री नितेश राणे से मुलाकात कर प्रतिबंध को 15 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की थी। मछुआरों का कहना था कि गुजरात में पहले से ही 1 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक रहती है, जिससे मछलियों की संख्या बढ़ी है और समुद्री संसाधनों का बेहतर संरक्षण हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि अगस्त के पहले पखवाड़े में समुद्र अक्सर खतरनाक बना रहता है, जिससे हादसों और आर्थिक नुकसान का खतरा रहता है।

अगले साल पूरे पश्चिमी तट पर एक समान नियम की तैयारी

मत्स्य मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात के मत्स्य मंत्री तथा मछुआरों के प्रतिनिधियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल जल्द ही केंद्रीय मत्स्य मंत्री से मुलाकात करेगा। इसमें अगले वर्ष से पूरे पश्चिमी तट पर 15 मई से 15 अगस्त तक एक समान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लागू करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे समुद्री जैव विविधता का संरक्षण होगा और मछुआरों की सुरक्षा भी बेहतर होगी।

ठाणे, नाशिक, बीड, अकोला सहित 259 पीएचसी और उपकेंद्रों में होगी नियुक्तियां

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण पूरा कर चुके 259 नए और श्रेणीवर्धित स्वास्थ्य संस्थानों के लिए 5,223 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। इन पदों पर होने वाले 320.01 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले से ठाणे, नाशिक, बीड, अकोला, पुणे, कोल्हापुर, छत्रपति संभाजीनगर सहित कई जिलों के अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी। इसी के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को गति और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में जारी शासनादेश के अनुसार राज्य में 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निर्माण पूरा कर चुकी 259 स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए कुल 7,955 पदों की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। इनमें से 2,732 पदों को पूर्व में मंजूरी दी जा चुकी थी, जबकि अब शेष 5,223 नए पदों के सृजन और संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के तहत ठाणे जिला अस्पताल को 336 से 500 बेड में उन्नत करने, बीड जिला अस्पताल को 300 से 500 बेड तक विस्तारित करने, ठाणे संदर्भ सेवा अस्पताल, ठाणे महिला अस्पताल, अकोला जिला अस्पताल, मंचर-अंबेगांव सामान्य अस्पताल, इचलकरंजी सामान्य अस्पताल और नाशिक संदर्भ सेवा अस्पताल सहित कई संस्थानों के लिए नए पद स्वीकृत किए गए हैं। नाशिक संदर्भ सेवा अस्पताल में बदलती स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार कई पुराने विशेषज्ञ पदों के स्थान पर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, जैव-चिकित्सा अभियंता, ईईजी व ईएमजी तकनीशियन सहित नए विशेषज्ञ पद सृजित किए गए हैं।

ग्रामिण अस्पतालों पर भी फोकस

इसके अलावा 13 ग्रामीण अस्पतालों को 30 से 50 बेड वाले उपजिला अस्पताल, छह ग्रामीण अस्पतालों को 30 से 100 बेड वाले उपजिला अस्पताल और छह उपजिला अस्पतालों को 50 से 100 बेड में उन्नत करने के लिए भी पदों का सृजन किया गया है। नए महिला अस्पतालों, पांच ट्रॉमा केयर यूनिट, चार आयुष अस्पताल, 13 नए ग्रामीण अस्पताल, 158 उपकेंद्र, 38 गैर-आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीन आदिवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, करमाड स्थित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र और राज्य स्तरीय औषधि भंडार के लिए भी नियमित पद स्वीकृत किए गए हैं।

ओसी मिलने के बाद भी होंगी नियुक्तियां

शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्तियां तभी की जाएंगी, जब इमारतों का निर्माण कार्य पूरी तरह पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी द्वारा ओसी जारी किया जाएगा। यदि किसी संस्था में पहले से स्वीकृत पदों की पुनरावृत्ति पाई जाती है तो उसे शासन की मंजूरी के बाद निरस्त किया जाएगा।

एसटी घाटे में रही तो जाएगी नौकरी!

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का कामचोर अधिकारियों को अल्टीमेटम

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र की जीवनरेखा मानी जाने वाली एमएसआरटीसी यानी एसटी बसों की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एमएसआरटीसी के उन अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं और जिनकी वजह से विभाग घाटे में जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगर अगले एक महीने में एसटी की आय में सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी महामंडल की गिरती आर्थिक स्थिति और राजस्व बढ़ाने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कामचोर और निष्कासन के पात्र अधिकारियों को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि अगले 30 दिनों के भीतर एसटी के राजस्व में ठोस वृद्धि और सकारात्मक परिणाम नहीं दिखे, तो संबंधित अधिकारियों का न केवल स्थानांतरण होगा, बल्कि उन्हें डिमोशन या सीधे निलंबन सस्पेंशन जैसी बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

21 विभाग घाटे में, आंकड़ों ने बढ़ाई सरकार की चिंता

एसटी प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वर्तमान में राज्य के कुल 31 एसटी विभागों में से 21 विभाग भारी घाटे में चल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अप्रैल और मई के गर्मी सीजन के दौरान, जब यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ होती है और किराए में भी बढ़ोतरी की गई थी, तब भी एसटी के राजस्व में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस विफलता ने प्रबंधन के नियोजन और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।

केवल दफ्तर में बैठने से काम नहीं चलेगा: सरनाईक के सख्त निर्देश

मंत्री प्रताप सरनाईक ने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल एसी दफ्तरों में बैठकर कागजी योजनाएं बनाना और लंबी बैठकों का दौर बंद करें। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारियों को अब जमीन पर उतरकर काम करना होगा। बस फेरों का सही नियोजन करना, गाड़ियों को निर्धारित समय पर डिपो से छोड़ना और यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देना अब उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। निजी वाहनों और निजी बस ऑपरेटरों के साथ मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा में एसटी को फिर से नंबर वन बनाने की जिम्मेदारी अब सीधे तौर पर अधिकारियों के कंधों पर डाल दी गई है।

कामकाज का होगा परफॉर्मेंस ऑडिट

दी गई एक महीने की समय सीमा समाप्त होने के बाद हर डिपो, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज का परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा कि किस अधिकारी के क्षेत्र में आय क्यों घटी और यात्री संख्या कम होने के पीछे क्या कारण रहे। मंत्री के इस आक्रामक तेवर ने एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारियों और डिपो प्रबंधकों के बीच हड़कंप मचा दिया है। अब अधिकारियों के पास केवल दो ही विकल्प हैं या तो वे अपनी कार्यकुशलता से एसटी को मुनाफे की पटरी पर वापस लाएं या फिर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

जालना में नशीली दवा जब्त, दो आरोपियों पर केस दर्ज

संयुक्त कार्रवाई में अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद

हिंदमाता नेटवर्क @ जालना

फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जालना और एंटी-स्मगलिंग ब्रांच, जालना ने एक जॉइंट ऑपरेशन में गैर-कानूनी तरीके से बिक्री के लिए हासिल की गई अल्प्राजोलम टैबलेट का स्टॉक जब्त किया है। मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर, इस ऑपरेशन में आरोपी शेख अफसर शेख अनवर, निवासी रिखी नगर, जालना के द्वारा कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका। ये दवाइयां नशे के लिए उपयोग किये जाने तथा बेचने के लिए एनज़िलम 0.5 (अल्प्राजोलम टैबलेट आईपी 0.5 मिलीग्राम) की 16 स्ट्रिप्स (कुल 240 टैबलेट) मिलीं, जिनकी कीमत लगभग 753/- थी।

दस्तावेज नहीं मिले

दवा खरीदने का बिल, डॉक्टर का सही प्रिस्क्रिप्शन या ड्रग सेल लाइसेंस नहीं दिखाया जा सका। टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए मौजूद स्टॉक से एक रैंडम सैंपल लिया गया और बरामद ड्रग स्टॉक को पुलिस ने पंचनामा बनाकर जब्त कर लिया।

मेडिकल स्टोर पर छापा

जांच के दौरान, आरोपी ने माना कि उसने ये दवाएं मिस्टर वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, कदराबा रोड, जालना से खरीदी थीं। इस जानकारी के आधार पर, संबंधित मेडिकल स्टोर पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान, एनज़िलम 0.5 (अल्प्राजोलम टैबलेट आईपी 0.5 मिलीग्राम) दवा की 76 स्ट्रिप्स (कुल 840 टैबलेट) मिलीं, जिनकी कीमत लगभग 3580/- थी। मिस्टर वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स के पास इन दवाओं की खरीद की रसीद नहीं थी।

1080 गोलियां जब्त

साथ ही, जांच के दौरान पाया गया कि यह दवा शेड्यूल ल्1 प्रिस्क्रिप्शन दवा है और इसका इंग्रीडिएंट एल्प्राजोलम एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत एक बैन चीज है। ये दवाएं बिना डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन और बिना सेल्स लाइसेंस के बेची जा रही थीं। नियमों के मुताबिक हेड स्टॉक से एक सैंपल लिया गया और टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए भेजा गया और बरामद दवा स्टॉक को पंचनाम के जरिए जब्त कर लिया गया है। इस ऑपरेशन में, दोनों जगहों से कुल 1080 गोलियां (240+840) जब्त की गईं और उनकी कुल कीमत 4333/- है।

आरोपियों पर कार्रवाई

शुरूआती जांच में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं और 'मे वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स', कद्रबन रोड, जालना में दवाइयां खरीदने और बेचने का काम लिखित आदेश जारी होने तक बंद करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में, आरोपी शेख अफसर शेख अनवर और विशाल शंकरप्पा दमतकरी के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 123 और 278, एनडीपीएस एक्ट, 1985 के सेक्शन 8(सी) और 22(ए) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के सेक्शन 18(ए), 18(सी) और 27(बी)(ii) के तहत क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई है।

एफडीए की चेतावनी

डॉक्टर के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के बिना अल्प्राजोलम जैसी साइकोट्रोपिक दवाओं का इस्तेमाल और गैर-कानूनी व्यापार न केवल ड्रग कानून का मामला है, बल्कि पब्लिक हेल्थ और हेल्थ सिस्टम के लिए भी एक गंभीर खतरा है। इसलिए, ऐसी दवाओं की गैर-कानूनी खरीद-बिक्री, गैर-कानूनी स्टोरेज या बिना इजाजत बांटने में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दवा बेचने वालों को दवा की खरीद का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए, नहीं तो उन्हें सख्त सजा का सामना करना पड़ेगा।

नई कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ रोहित पवार का विरोध-प्रदर्शन

हिंदमाता नेटवर्क @ संभाजीनगर

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और करजत-जामखेड़ विधायक रोहित पवार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर में सरकार की नई कृषि ऋण माफी योजना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो 'जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

पंढरपुर अनशन का हवाला

पवार ने कहा कि इसी महीने पंढरपुर में उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसे सरकार की बैठक के आश्वासन पर समाप्त किया गया था। लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई। मंत्री गिरीश महाजन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।

रोहित पवार का हमला

सरकार ने दो जून को 36,585 करोड़ रुपए की 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ति योजना' को मंजूरी दी थी। योजना में अधिकतम दो लाख रुपए तक की माफी का प्रावधान है, लेकिन पवार पूर्ण ऋण माफी और सभी प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटाने की मांग कर रहे हैं।

आंदोलन कुचलने की कोशिश का आरोप

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल, दंगा नियंत्रण बल सहित करीब 1,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। पवार ने कहा कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है। आगे की रणनीति किसानों से चर्चा के बाद तय की जाएगी। उन्होंने मांग की कि पात्र किसानों को बिना किसी शर्त के पूर्ण ऋण माफी दी जाए। योजना के तहत दो लाख रुपए तक के बकाया वाले किसानों को माफी मिलेगी। दो लाख से अधिक बकाया वालों को एकमुश्त समझौते के तहत दो लाख रुपए माफ किए जाएंगे, बाकी राशि उन्हें जमा करनी होगी।

बिना किराया बढ़ाए मध्य रेल की कमाई में उछाल

दो महीने में 20 .48 करोड़ का गैर-किराया राजस्व

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

यात्रियों पर किराए का अतिरिक्त बोझ डाले बिना मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में गैर-किराया राजस्व बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। मई 2026 तक मध्य रेल ने 20.48 करोड़ रुपए का गैर-किराया राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 17.54 करोड़ रुपए की तुलना में 16.78 प्रतिशत अधिक है। विज्ञापन, होर्डिंग, रेल कोच रेस्तरां, वाणिज्यिक सुविधाओं और अन्य परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के जरिए रेलवे ने आय के नए स्रोत विकसित किए हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। राजस्व बढ़ाने के लिए मध्य रेल ने ट्रेनों और रेलवे परिसंपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाया है।

नवोन्मेषी योजनाएं लागू कर रही है मध्य रेल

मुंबई मंडल ने महानगरी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, सीएसएमटी-लातूर, सीएस एमटी-बीदर और वंदे भारत एक्सप्रेस में बहरी और आंतरिक विज्ञापनों के लिए बहुवर्षीय अनुबंध किए है। इसके अलावा लोकमान्य तिलक टर्मिनस में रेल कोच रेस्तरां, प्रतीक्षालय-सह-कैटीन, किराना व फोटोकॉपी केंद्र, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, ऑन-बोर्ड बिक्री, मोबाइल चार्जिंग कियोस्क, मोबाइल फूड वैन, डिजिटल लॉकर और ट्रक पार्किंग जैसी सुविधाओं के संचालन के लिए भी विभिन्न मंडलों में कई अनुबंध प्रदान किए गए है।

4.09 करोड़ से अधिक का लाइसेंस शुल्क प्राप्त

बताया गया है कि ई-नीलामी के माध्यम से 29 अनुबंध प्रदान किए गए जिनसे प्रतिवर्ष 4.09 करोड़ रुपए से अधिक का लाइसेंस शुल्क प्राप्त होगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ.स्वप्नील निला ने बताया कि मध्य रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ रेल परिचालन को प्रभावित किए बिना अपनी परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के जरिए गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार नवोन्मेषी योजनाएं लागू कर रही है।

महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी सड़कों पर होर्डिंग के नियम सख्त

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के नियमों को और सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के तहत अब राज्य भर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने के सभी प्रस्तावों को संबंधित मुख्य अभियंता स्तर पर मंजूरी दी जाएगी। विज्ञापन लगाने की अनुमति केवल 5 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी और इसकी अवधि पूरी होने के बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय संबंधित स्थान का आवंटन नई ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही होर्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट और मानसून के दौरान विशेष निरीक्षण भी अनिवार्य किए गए हैं।

एमवीए की बैठक से 24 विधायक रहे गैरहाजिर

महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

महाविकास आघाड़ी (मविआ) के 24 विधायकों की बैठक से गैर हाजिरी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और मंत्री उदय सामंत ने इन विधायकों की नाराजगी का जिक्र करते हुए संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में 'मविआ' को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया कि अब किसी 'ऑपरेशन टाइगर' की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कई जनप्रतिनिधि खुद ही शिंदे गुट के साथ आने के इच्छुक हैं। उदय सामंत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की मुंबई बैठक में 24 विधायक शामिल नहीं हुए।

विधायकों के मन में नेतृत्व को लेकर नाराजगी

उनके मुताबिक, यह केवल संयोग नहीं है बल्कि इन विधायकों के मन में नेतृत्व को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट इन विधायकों से बातचीत करेगा और यदि कोई स्वेच्छा से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाएगा।

वहां कोई रहना ही नहीं चाहता है : शिरसाट

सामंत के दावे को बल देते हुए सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के 6 सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद अब विधायकों के दल बदलने की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट को 'ऑपरेशन टाइगर-3' चलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई विधायक और जनप्रतिनिधि खुद ही ठाकरे गुट में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि जो भी उनके साथ आना चाहेगा उसे पूरा सहयोग दिया जाएगा।

हिंदमाता एंकरः बदबू, बाढ़ और बीमारियों के बीच जीवन, बोले- सीवेज नहीं बेहतर आवास चाहिए

धारावी के लोगों का छलका दर्द

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

इस में देरी से हर कोई साल मुंबई में मानसून में चिंतित है। इस कारण भविष्य में पानी की कमी से निपटने के लिए मुंबई मनपा प्रदूषित गंदे पानी को पीने लायक पानी में बदलने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। ऐसे में धारावी के कई निवासियों का कहना है कि हमें सीवेज का पानी पीने के लिए न कहें, बल्कि हमें इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करें। दशकों से धारावी में हजारों परिवार मुंबई के सबसे गंदे नालों और प्रदूषित जल निकायों के किनारे रह रहे हैं। उन्हें असहनीय बदबू, बाढ़, मच्छरों और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

घरों में भर जाता है गंदा पानी

धारावी के कुछ हिस्सों से गुजरने वाली काली और धीमी गति से बहने वाली जलधाराएं बिना ट्रीट किए गए सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक और कचरे से भरी हुई हैं। यहां से कुछ ही फुट की दूरी पर रहने वाले लोगों के लिए यह कोई काल्पनिक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि रोजाना का संघर्ष है। धारावी की एक गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता जुबेदा खान ने कहा कि लोग उस पानी को पीने की कल्पना नहीं कर सकते, जो कभी इन नालों से बहता था। बदबू हमारे घरों में प्रवेश करती है, मच्छर यहां पनपते हैं और मानसून के दौरान गंदा पानी हमारे घरों में भर जाता है। हमें पुनर्विकास के माध्यम से बेहतर आवास और स्वच्छ वातावरण की जरूरत है।

बढ़ जाता है बीमारियों का खतरा

स्वास्थ्य पर प्रभाव सभी आयु सम्मूहों पर दिखाई देता है। बच्चे खुली नालियों के बगल में संकरी गलियों में खेलते हुए बड़े होते हैं, जबकि कई बुजुर्ग निवासी मांस लेने में समस्या, त्वचा में संक्रमण और बार-बार होने वाली बीमारियों की शिकायत करते हैं। निवासियों का कहना है कि बड़ा मुद्दा यह नहीं है कि क्या गंदे पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है, बल्कि यह है कि लोगों को जहरीली नालियों के किनारे क्यों रहना चाहिए। इसका समाधान धारावी पुनर्विकास परियोजना में तेजी लाने में निहित है। जो आधुनिक आवास, उचित स्वच्छता, भूमिगत जल निकासी और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन का वादा करती है। पुनर्विकास केवल बुनियादी ढांचे में सुधार से कहीं अधिक कर सकता है। यह प्रदूषण को कम करके, स्वास्थ्य में सुधार करके जीवन की गुणवत्ता में मौलिक परिवर्तन ला सकता है। धारावी में पुनर्विकास केवल नए घरों के बारे में नहीं है। यह एक ऐसे वातावरण से मुक्ति पाने के बारे में है जिसने दशकों से स्वास्थ्य और गरिमा को धूमिल किया है।

बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक के पास मिला हंपबैक व्हेल का शव

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई में उस समय सनसनी फैल गई जब बांद्रा-वसोर्वा सी लिंक के पास ओटर्स क्लब के नजदीक चट्टानों के बीच एक हंपबैक व्हेल का बच्चा फंसा हुआ पाया गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें व्हेल का शव चट्टानों के बीच फंसा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार, यह हंपबैक व्हेल लगभग 26 फीट लंबी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड और बांद्रा-वसोर्वा सी लिंक प्रोजेक्ट की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जांच के बाद व्हेल को मृत घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने क्रेन की मदद से बेहद सावधानीपूर्वक व्हेल के शव को चट्टानी इलाके से बाहर निकाला। इसके बाद उसे सुरक्षित तरीके से हटाकर दफनाने के लिए ले जाया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण नियमों का विशेष ध्यान रखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि समुद्र की तेज लहरें किनारे से टकरा रही थीं और मौसम भी खराब स्थिति में था। व्हेल का शव चट्टानों के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर लोगों में चिंता और हैरानी दोनों देखी गई।

विचार प्रवाह

बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। मेरे पास बस एक दिन है, और मैं इसमें खुश रहूंगा।

- ग्रुशो मार्क्स

संपादकीय

घुसपैठियों की पहचान

देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की मजबूती और सरकारी संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए अवैध घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। इसी संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक बुलाकर घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की रूपरेखा तैयार करना एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यदि यह अभियान प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो इससे वर्षों से चली आ रही इस चुनौती से निपटने की दिशा में ठोस प्रगति संभव हो सकती है। अब तक विभिन्न राज्यों में अपने-अपने स्तर पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और कार्रवाई के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि किसी एक राज्य में अभियान शुरू होने की सूचना मिलते ही संदिग्ध लोग दूसरे राज्यों में चले जाते थे। इस कारण कार्रवाई अधूरी रह जाती थी और समस्या जस की तस बनी रहती थी। इसलिए पूरे देश में एक साथ, समन्वित और योजनाबद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या समुदाय के लोगों की वास्तविक संख्या का सटीक आकलन करना आसान नहीं है। हालांकि विभिन्न राज्यों में समय-समय पर हुई कार्रवाइयों से यह स्पष्ट होता है कि वे अनेक हिस्सों में फैले हुए हैं। कई मामलों में उनके पास आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज मिलने की घटनाएं भी सामने आई हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से पहचान पत्र प्राप्त कर लिया है, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी गंभीर प्रश्न बन जाता है। इस समस्या की एक और गंभीर कड़ी उन संगठित गिरोहों से जुड़ी है, जो कथित रूप से सीमाओं के पार से लोगों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराने, उनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और उन्हें विभिन्न राज्यों में बसाने का काम करते हैं। जब तक ऐसे नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक केवल घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया स्थायी समाधान नहीं बन सकती। इसलिए जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस को इस पूरे तंत्र की जड़ों तक पहुंचकर कार्रवाई करनी होगी। अवैध घुसपैठ केवल जनसंख्या का प्रश्न नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सरकारी योजनाओं के उचित लाभार्थियों से भी जुड़ा विषय है। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अनुमति के देश में रहकर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता है, तो इसका सीधा असर उन नागरिकों पर पड़ता है, जो कानूनी रूप से इन योजनाओं के हकदार हैं। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध बसावट स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियां समय-समय पर यह भी संकेत देती रही हैं कि कुछ मामलों में अवैध घुसपैठ का इस्तेमाल आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे में सतर्कता और सख्ती दोनों आवश्यक हैं। हालांकि इस पूरे अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और तथ्यों के आधार पर हो। किसी भी भारतीय नागरिक को केवल भाषा, वेशभूषा, धर्म या क्षेत्रीय पहचान के आधार पर संदेह के घेरे में नहीं लाया जाना चाहिए। पहचान की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और दस्तावेजी प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि निर्दोष लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है। अंततः केवल घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेज देना पर्याप्त नहीं होगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सीमाओं की निगरानी और अधिक सुदृढ़ करनी होगी। आधुनिक तकनीक, प्रभावी सीमा प्रबंधन, राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय तथा अवैध दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों पर कठोर कार्रवाई-ये सभी कदम समान रूप से आवश्यक हैं। यदि इन सभी पहलुओं पर एक साथ गंभीरता से काम किया जाए, तभी देश अवैध घुसपैठ की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत आधार प्रदान किया जा सकेगा।

आज का इतिहास

■ 1999 - आस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टीम फिशर का इस्तीफा।
■ 2002 - ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबाल के विश्व कप पर कब्जा किया।
■ 2003 - चार आस्कर पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का निधन।
■ 2005-ब्राजील ने कनफेडरेशन फुटबाल कप जीता।
■ 2006-फुटबाल विश्वकप में जर्मनी ने अर्जेन्टीना को हराया।
■ 2007 - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया।
■ 2008 -रविकांत, उमा शंकर चौधरी व विमल चन्द्र पाण्डेय को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसियेशन आफ बुक कीपर्स (आईएबी) के न्यू बिजनेस आफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने कबाइली खैबर दर्रा क्षेत्र में दहशत फैला रहे तीन आतंकी गुटों पर प्रतिबन्ध लगाया। राबर्ट मुगावे ने जिम्बाव्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
■ 1969 - भूपेन्द्र यादव - भारतीय राजनीतिज्ञ और राज्य सभा के सांसद हैं।
■ 1911 - नागार्जुन - भारतीय साहित्यकार।
■ 1921 - रघुवंश - हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक थे।
■ 1928 - कल्याणजी - हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकर।
■ 1934 - सी. एन. आर. राव - भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक।
■ 1956 - हरिवंश नारायण सिंह - भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं।
■ 1903 - मुकुट बिहारी लाल भार्गव - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक सभा के सदस्य थे।
■ 2007 - साहिब सिंह वर्मा - भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व तेरहवीं लोक सभा के सांसद थे।
■ 1985-के. एच. आरा - भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
■ 1970 - आशा देवी आर्यनायकम - एक समर्पित महिला थीं जिन्होंने अनभिज्ञता को दूर करने और ज्ञान, प्रेम और विश्वास से भरी दुनिया बनाने की कोशिश की।
■ 1917 - दादा भाई नौरोजी - भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक।

पेपर लीकः टूटता भरोसा, बिखरते सपने

परीक्षा व्यवस्था में बढ़ती सेंध, लाखों युवाओं के भविष्य पर सीधा हमला

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

जिस तरह क ोई संक्रामक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तेजी से फैलती है, उसी तरह देश में इन दिनों पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के पेपर लीक का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब शिक्षक बनने के लिए आवश्यक टीईटी परीक्षा का प्रश्नपत्र भी लीक हो गया। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि परीक्षा व्यवस्था में नीचे से लेकर ऊपर तक गंभीर खामियां मौजूद हैं। यह केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार है। लाखों विद्यार्थी वर्षों की मेहनत, अपने परिवार की उम्मीदों और बेहतर भविष्य के सपनों के साथ परीक्षा देते हैं। ऐसे में बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाएं उनके मन में यह सवाल खड़ा कर देती हैं कि आखिर ईमानदारी से मेहनत करने का क्या फायदा?

हर बार वही आश्वासन, नतीजा शून्य

पेपर लीक की घटनाएं अब अपवाद नहीं, बल्कि एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन चुकी हैं। कभी नीट, कभी प्रतियोगी परीक्षाएं तो कभी शिक्षक पात्रता परीक्षा—लगातार एक के बाद एक प्रश्नपत्र लीक होने के बावजूद ठोस सुधार दिखाई नहीं देता। हर घटना के बाद सरकार की ओर से जांच, दोषियों पर कार्रवाई और कठोर कदम उठाने की घोषणा की जाती है, लेकिन समय बीतने के साथ ये घोषणाएं केवल औपचारिकता बनकर रह जाती हैं। परीक्षार्थियों का भरोसा इन आश्वासनों से लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जांच के नाम पर अक्सर केवल छोटे स्तर के लोगों पर कार्रवाई होती है, जबकि पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले असली मास्टरमाइंड कानून की पकड़ से बाहर ही रहते हैं।

सुरक्षा के बावजूद आखिर लीक कैसे?

■ सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है, तब भी पेपर बाहर कैसे आ जाता है? डिजिटल एन्क्रिप्शन, सीलबंद पैकेट, गोपनीय परिवहन, जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी और पुलिस सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद यदि प्रश्नपत्र लीक हो रहा है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि समस्या व्यवस्था के भीतर ही कहीं गहराई तक फैली हुई है। बिना अंदरूनी मिलीभगत, भ्रष्टाचार और पैसों के प्रभाव के ऐसी घटनाएं संभव नहीं हैं। इसलिए केवल बाहरी जांच से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही तय करनी होगी।

सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं विद्यार्थी

■ पेपर लीक का असर न तो नेताओं पर पड़ता है, न अधिकारियों पर और न ही प्रश्नपत्र बेचने वाले गिरोहों पर। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उन विद्यार्थियों पर पड़ता है, जिन्होंने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया होता है। कई छात्र नौकरी छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। अनेक परिवार कर्ज लेकर बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं। मध्यमवर्गीय परिवार अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जब परीक्षा रद्द होती है तो केवल एक परीक्षा स्थगित नहीं होती, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक पूंजी भी बिखर जाती है। बार-बार परीक्षा टलने से युवाओं में निराशा, अवसाद और व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी बढ़ता है।

शिक्षक चयन पर उठते गंभीर सवाल

टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि यह सीधे उन लोगों के चयन से जुड़ा है जो आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारेंगे। यदि शिक्षक बनने की प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो शिक्षा व्यवस्था की नींव कमजोर होना स्वाभाविक है। इससे यह गलत संदेश जाता है कि सफलता योग्यता और मेहनत से नहीं, बल्कि पैसे और पहुंच के बल पर हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, जो शिक्षक पहले से सेवा में हैं और पदोन्नति या सेवा की निरंतरता के लिए टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी यह गहरा अन्याय है। पहले से ही गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे शिक्षकों के लिए ऐसी घटनाएं मानसिक पीड़ा को और बढ़ा देती हैं।

पेपर लीक बनता जा रहा है संगठित कारोबार

आज पेपर लीक केवल कुछ लोगों की साजिश नहीं रह गया है, बल्कि यह एक संगठित उद्योग का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसमें प्रश्नपत्र चुराने वाले, उसे बेचने वाले, दलाल, तकनीक का दुरुपयोग करने वाले, सोशल मीडिया पर गुप्त समूह चलाने वाले और उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों की पूरी श्रृंखला सक्रिय रहती है। यही संगठित नेटवर्क इस अपराध को लगातार बढ़ावा देता है। यदि इस कड़ी को नहीं तोड़ा गया, तो भविष्य में और भी बड़ी परीक्षाएं इसकी चपेट में आ सकती हैं।

अब केवल कार्रवाई नहीं, स्थायी समाधान चाहिए

समय आ गया है कि सरकार केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया देने की बजाय पहले से रोकथाम करने वाली मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी या मुकदमा दर्ज कर देना अब पर्याप्त नहीं है। पेपर लीक को अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर त्वरित न्याय सुनिश्चित करना होगा। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक, स्वतंत्र निगरानी, जवाबदेही और पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। आखिर प्रश्नपत्र के साथ केवल कागज के कुछ पन्ने नहीं लीक होते, बल्कि देश के लाखों युवाओं के सपने भी टूटते हैं। इसलिए इस अपराध को किसी प्रशासनिक चूक के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य पर किए गए गंभीर प्रहार के रूप में देखा जाना चाहिए।

आंखनदेखी

शैमोनी, फ्रांस में भीषण गर्मी के बीच पर्वतारोही एगुइय दु मिडी पर्वत शिखर के पास आगे बढ़ते हुए। लगातार बढ़ते तापमान के कारण आल्प्स के हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पर्यावरण विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों और भविष्य में बढ़ते प्राकृतिक खतरों को लेकर चिंता जताई है।

किशोरों की सुरक्षा संवाद ही सबसे बड़ी ढाल

●चिंताजनक घटनाओं से मिलती चेतावनी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

हाल ही में ब्रिटेन की संसद में ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर हुई बहस ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। पिछले दो दशकों में वहां हजारों किशोरियां और बालिकाएं संगठित गिरोहों द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई हैं। संसद में गृह सचिव ने स्वीकार किया कि कई मामलों में पाकिस्तानी मूल के कुछ टैक्सी चालक और व्यापारी भी आरोपी थे। यह बहस भारत के उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाती है, जब वर्ष 1992 में राजस्थान के अजमेर में 100 से अधिक स्कूली और कॉलेज छात्राओं के यौन शोषण तथा ब्लैकमेल का मामला सामने आया था। इस मामले में विशेष अदालत ने कई आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन बाद में कुछ दोषियों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई। ऐसी घटनाएं केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि समाज और परिवार के सामने खड़ी गंभीर चुनौती भी हैं।

विश्वास जीतकर बिछाया जाता है जाल

इस प्रकार के अधिकांश अपराध अचानक नहीं होते, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले पीड़ित का विश्वास जीता जाता है, फिर उससे भावनात्मक संबंध बनाए जाते हैं और धीरे-धीरे उसकी सोच, निर्णय और अंततः उसकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाती है। शुरूआत में सब कुछ सामान्य मित्रता या अपनत्व जैसा दिखाई देता है, लेकिन समय के साथ यह संबंध शोषण और ब्लैकमेल का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे अपराधों की पहचान करना कई बार कठिन हो जाता है।

किशोरावस्था का सबसे संवेदनशील दौर

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे संवेदनशील चरण होती है। इसी उम्र में व्यक्ति अपनी पहचान बनाने और समाज में अपनी जगह खोजने का प्रयास करता है। इस समय उसे मित्रता, स्वीकृति, सम्मान और अपनत्व की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से किसी किशोर या किशोरी को विशेष महत्व देने का एहसास कराए, उसकी भावनाओं को समझने का दिखावा करे और उसका विश्वास जीत ले, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। कई बार किशोर यह समझ ही नहीं पाते कि जिसे वे सच्चा प्रेम या अपनापन मान रहे हैं, वह वास्तव में एक सोची-समझी साजिश का

व्यस्त जीवन में संवाद का महत्व

आज समाज तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है और माता-पिता कामकाजी जीवन में पहले से अधिक व्यस्त हो गए हैं। ऐसे माहौल में बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन कई बार उन्हें परिवार का पर्याप्त समय और भावनात्मक सहयोग नहीं मिल पाता। बच्चों को केवल अच्छे स्कूल, महंगे मोबाइल या आधुनिक सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें अपने माता-पिता की उपस्थिति, विश्वास और संवाद की भी आवश्यकता होती है। यदि परिवार बच्चों के मन की बात सुनने और उनकी भावनाओं को समझने के लिए समय निकाले, तो कई संभावित खतरे शुरूआती स्तर पर ही टाले जा सकते हैं।

सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी परिवार की

हर व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा और अपनत्व की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता सबसे पहले परिवार के भीतर पूरी होनी चाहिए। परिवार केवल भोजन, शिक्षा और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वह विश्वास, संवाद, आत्मीयता और सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार भी होता है। जब माता-पिता और बच्चों के बीच खुलकर बातचीत नहीं होती या बच्चे अपनी परेशानियां साझा करने से हिचकने लगते हैं, तब उनके और परिवार के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में वे अपनेपन की तलाश घर से बाहर करने लगते हैं, जहां कई बार गलत लोग उनका फायदा उठा लेते हैं।

सतर्कता और संवेदनशीलता दोनों जरूरी

किशोरों की सुरक्षा का अर्थ उनकी हर गतिविधि पर संदेह करना या उनकी निजता का उल्लंघन करना नहीं है। अत्यधिक निगरानी भी कई बार बच्चों और अभिभावकों के बीच दूरी बढ़ा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार, विद्यालय और समाज बच्चों के व्यवहार, मित्र मंडली, दिनचर्या, मानसिक स्थिति और डिजिटल गतिविधियों में होने वाले असामान्य परिवर्तनों पर संवेदनशीलता से ध्यान दें। यदि कोई बदलाव दिखाई दे तो डांटने या आरोप लगाने के बजाय उनसे खुलकर संवाद किया जाए। विश्वास का वातावरण ही बच्चों को सही समय पर अपनी समस्याएं साझा करने का साहस देता है।

प्रेरक प्रसंग

दो आदमी

अंग्रेजी फिल्मों का मुझे बचपन से ही शौक था। अक्सर देर रात का शो देखकर मैं आधी रात के बाद घर लौटता था। उस समय सड़कें सुनसान होतीं और घर पहुंचने का एकमात्र सहारा रिक्शा ही होता। एक रात जब मैं घर पहुंचा तो रिक्शे का किराया देने के लिए जेब टटोली। मेरे पास केवल पांच रुपए का नोट था, जबकि रिक्शावाले के पास छुट्टे नहीं थे। आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। मैंने उसे पांच का नोट देते हुए कहा, "अगले चौराहे से खुलवा लाओ।" वह नोट लेकर चला गया। उसके जाते ही मेरे मन में तरह-तरह के संदेह उठने लगे। कहीं वह नोट लेकर भाग न जाए? मैंने अनायास ही उसके रिक्शे का नंबर याद कर लिया, ताकि जरूरत पड़ने पर पुलिस में शिकायत कर सकूं। मन बार-बार कह रहा था कि शायद वह अब वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वह दौड़ता हुआ लौटा। उसने मुस्कुराकर पूरे पांच रुपए की रेजगारी मेरे हाथ पर रख दी। उसके चेहरे पर ईमानदारी थी और मेरे चेहरे पर शर्म। उस रात मुझे अपनी सोच पर ग्लानि हुई। मैंने बिना किसी कारण एक मेहनतकश इंसान पर शक किया था। मुझे लगा कि विश्वास करने से पहले ही मैंने उसे बेईमान मान लिया था। कुछ दिनों बाद फिर वही संयोग बना। आधी रात का शो देखकर लौटा तो जेब में केवल दो रुपए का एक नोट बचा था। इस बार भी रिक्शावाले के पास छुट्टे नहीं थे और बाजार की सारी दुकानें बंद थीं। मैंने उसे दो रुपए का नोट दिया और कहा, "कहीं से खुलवा लाओ।"

■ इस बार मैंने जानबूझकर उसके रिक्शे का नंबर नहीं देखा। पिछले अनुभव ने मुझे सिखा दिया था कि हर आदमी पर शक करना ठीक नहीं। मुझे पूरा विश्वास था कि वह लौट आएगा। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार करता रहा। मिनट बीतते गए, फिर आधा घंटा गुजर गया। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन वह रिक्शावाला वापस नहीं आया। उस रात मेरे मन में एक अजीब-सी टीस उठी। मैं सोचने लगा-पहली बार मैंने एक ईमानदार आदमी पर संदेह किया था।

■ इसलिए शर्मिंदा हुआ। दूसरी बार मैंने उसी अनुभव के भरोसे एक अनजान आदमी पर विश्वास कर लिया और ठगा गया। तभी मुझे समझ आया कि दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं-एक जो विश्वास को निभाते हैं और दूसरे जो उसी विश्वास का फायदा उठाते हैं। असली बुद्धिमानी न हर किसी पर शक करने में है और न ही आंख मूंदकर भरोसा करने में, बल्कि सही व्यक्ति की पहचान करने में है।

राशिफल

मेष- शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड इत्यादि से लाभ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। जल्दबाजी न करें। लेनदारी वसूल करने के प्रयास सफल रहेंगे। व्यावसायिक यात्रा मनोनुकूल रहेगी। भाग्य का साथ रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। समय पर कर्ज चुका पाएंगे।

वृषभ-नई आर्थिक नीति बन सकती है। कार्यस्थल पर सुधार व परिवर्तन से भविष्य में लाभ होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पार्टनरों का सहयोग कार्य में गति प्रदान करेगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। पुराना रोग उभर सकता है। शारीरिक कष्ट संभव है।

मिथुन- लाभ के अवसर हाथ आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। नौकरी में उन्नति होगी। निवेशादि करने का मन बनेगा। विवेक से कार्य करें, लाभ होगा। शत्रु सक्रिय रहेंगे। परिवार की चिंता बनी रहेगी। धार्मिक कार्य में मन लगेगा।

कर्क- धनागम होगा। प्रतिद्वंद्वी अपना रास्ता छोड़ देंगे। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। किसी भी प्रकार के झगड़ों में न पड़ें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

सिंह- रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सभी ओर से खुश खबरें प्राप्त होंगी। पारिवारिक चिंता रहेगी। अज्ञात भय सताएगा। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। संपत्ति की खरीद-फरोख्त में सफलता मिलेगी।

कन्या- आय के साधनों में वृद्धि होगी। भाग्योन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। भूमि व भवन संबंधी कार्य लाभदायक रहेंगे। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शेयर मार्केट व म्युचुअल फंड में निवेश लाभदायक रहेगा।

तुला-लाभ के अवसर हाथ आएंगे। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में संतोष रहेगा। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। शारीरिक कष्ट संभव है। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी।

वृश्चिक- किसी अपरिचित व्यक्ति पर अतिविश्वास न करें। व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। पुराना रोग उभर सकता है। दुःखद समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाद से क्लेश संभव है। जोखिम व जमानत के कार्य टालें।

धनु- व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। शेयर मार्केट मनोनुकूल लाभ देंगे। कानूनी अड़चन सामने आएगी। अज्ञात भय सताएगा। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

मकर- नौकरी में अधिकार मिल सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होगा। बाहर जाने का मन बनेगा। बड़ा काम करने की योजना बनेगी। लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी व्यक्ति के व्यवहार से स्वाभिमान को ठेस पहुंच सकती है। शुभ समाचार प्राप्त होंगे।

कुंभ- अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। सट्टे व लॉटरी से दूर रहें। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। सुख के साधनों पर व्यय होगा। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। निवेश शुभ रहेगा। चोट व रोग से बचें। यश बढ़ेगा। बेचैनी रहेगी।

मीन-व्यवसाय ठीक चलेगा। आय बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट से बाधा संभव है। अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। हल्की हंसी-मजाक न करें। किसी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा न करें। चिंता तथा तनाव रहेंगे। लेन-देन में जल्दबाजी न करें।

राम मंदिर चढ़ावा विवादः सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से साफ इनकार, पूछा- आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और ट्रस्ट के पैसों के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़े मामले में एक बड़ी और अहम कानूनी खबर सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए तीखी टिप्पणी की और पूछा कि आखिर इस मामले को इतनी जल्दी सुनने की क्या जरूरत है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले पर कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही नियमित तौर पर सुनवाई की जाएगी।

■ सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पैसों और श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगें उठाई थीं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ट्रस्ट के पैसों के लेन-देन में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं इसलिए इस मामले में तुरंत एक आपराधिक एफआईआर (xxxx) दर्ज की जानी चाहिए। याचिका में सिर्फ पुलिस एफआईआर की मांग नहीं थी बल्कि यह भी कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (xxxx) का गठन किया जाए जिसकी कप्तानी केंद्रीय जांच ब्यूरो (उइक) के किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए।

■ याचिकाकर्ता चाहते हैं कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी (Court-Monitored Investigation) में हो और इसके लिए एक डेडलाइन (तय समय सीमा) निर्धारित की जाए ताकि जांच में देरी न हो। वहीं जब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत की पीठ के सामने आया तो याचिकाकर्ता के वकील ने इस पर 'अर्जेंट हियरिंग' (तुरंत सुनवाई) और फौरन आदेश जारी करने का पुरजोर आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को देखने के बाद तत्काल सुनवाई की आवश्यकता को खारिज कर दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से सीधा सवाल पूछा कि इस याचिका को अभी के अभी सुनने जैसी कोई गंभीर या आपातकालीन वजह नजर नहीं आती तो फिर इसमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है?

■ तत्काल राहत देने से मना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन (सर्दियों/गर्मियों की छुट्टियां) खत्म होने और कोर्ट के दोबारा पूरी तरह खुलने के बाद ही सूचीबद्ध (List) किया जाएगा। इसका साफ मतलब यह है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े इस विवाद पर कानूनी कार्यवाही शुरू होने में अभी याचिकाकर्ता को कुछ समय का इंतजार करना होगा।

भाजपा की 'नजर नेशन पर नहीं डोनेशन' परः अखिलेश यादव

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'नजर नेशन पर नहीं, डोनेशन पर' (देश पर नहीं दान पर) रहती है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया।

भाजपा के शब्दकोष में न धर्म है और न शर्म

पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, यादव ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और प्रसाद की कथित चोरी को लेकर आरोप लगाया कि यह भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में चौतरफा लूट है। भाजपा के शब्दकोष में न धर्म है और न शर्म। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी आस्था के साथ खिलवाड़ है।

भाजपा का ध्यान देश से ज्यादा दान पर

यादव ने दावा किया कि अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के तार कर्नाटक से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां 'गैर-पंजीकृत और भूमिगत' लोग चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनावी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। यादव ने कहा कि भाजपा का ध्यान देश से ज्यादा दान पर है। उन्होंने चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि चोर-चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई भगवान राम की पाई।

भाजपा ने भगवान राम को धोखा दिया

सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मामले में केवल 'छोटी मछलियां' पकड़ी जा रही हैं, जबकि 'बड़ी मछलियों' को बचाया जा रहा है। उन्होंने स्वयं को 'सच्चा सनातनी' मानने वाले लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने और पार्टी से चुनाव टिकट नहीं मांगने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा ने भगवान राम को धोखा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा सीसीटीवी से डरती है, क्योंकि लोग अब 'सीसी' का मतलब समझ चुके हैं, चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी।

करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा सफाई में विफल भाजपा

यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हाल में लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने जैसी घटनाएं भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम हैं, जिनमें विद्यार्थियों और नौकरी के अभ्यर्थियों की जान गई। उन्होंने भाजपा सरकार पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा की सफाई में विफल रहने का भी आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष ने प्रयागराज में आयोजित सपा के 'विजन इंडिया' कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। यादव ने कहा कि अगर 2027 में सपा की सरकार बनती है तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

चंपत राय और अनिल मिश्रा को बार एसोसिएशन की चेतावनी; रामनगरी की सियासत गरमाई

3 दिन में अयोध्या छोड़ें

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने तूल पकड़ लिया। यूपी सराकर द्वारा गठित एसआईटी की टीम मामले की जांच करते हुए लगातार एक के बाद एक कई खुलासे किए हैं। अब इस केस में अयोध्या बार एसोसिएशन भी कूद पड़ा है। बार एसोसिएशन ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को तीन दिनों के अंदर अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। अयोध्या बार एसोसिएशन के लोगों ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी। गौरतलब है कि अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में बार एसोसिएशन की एंट्री ने इस मामले को आग में घी देने का काम किया है।

बार एसोसिएशन की बैठक में फैसला

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले के बीच बार एसोसिएशन के सदस्यों की हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएश के सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को राम नगरी से दूर जाना होगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि ट्रस्ट से जुड़े इन तीनों लोगों को अयोध्या राम नगरी को छोड़ना होगा। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर 3 दिन के भीतर वे अयोध्या नहीं छोड़ते हैं तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, किसी को भी अयोध्या आने की एंट्री नहीं मिलेगी।

आरोपियों के रखने वालेवकीलों पर जुर्माना

अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई भी वकील अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। अगर कोई भी वकील ऐसा करता है तो उसे पहले बार एसोसिएशन के योगदान फंड में एक प्रति आरोपी 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीआरपीसी की धारा 173 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस घटना के लिए सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो अयोध्या अधिवक्ता संघ अपने खर्चे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। गौरतलब है कि इस समय यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच अधिवक्ताओं की एंट्री ने इस केस को और दिलचस्प बना दिया है।

राम मंदिर के चोरों को नहीं मिलेगा कोई वकील!

अयोध्या बार एसोसिएशन का बड़ा ऐलान, केस लड़ा तो भुगतना होगा अंजाम

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जनता में गुस्सा भरा हुआ है। यही गुस्सा और आक्रोश अब वकीलों में भी देखा गया है। एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं। इन आरोपियों का केस लड़ने के लिए अब कोई वकील सामने नहीं आ रहा है। फैजाबाद एडवोकेट्स एसोसिशन ने आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मुहीम छेड़ दी है। वकीलों ने ऐलान कर दिया है कि शहर का कोई भी वकील राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फंसे आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर किसी ने आरोपियों का केस लड़ा तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।

केस लड़ा तो भुगतना होगा अंजाम

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी कथित हेराफेरी के मामले को लेकर फैजाबाद एडवोकेट्स एसोसिएशन की बैठक हुई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा और अगर कोई ऐसा करता है, तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

चंपत राय को अयोध्या छोड़ने की दी चेतावनी

बार एसोसिएशन की बैठक में सभी वकीलों ने इस फैसले का स्वागत किया। वकीलों ने जोर देकर कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को जल्द-से-जल्द अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 दिन के अंदर तीनों ने अयोध्या नहीं छोड़ा तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा और किसी को भी अयोध्या के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी से जुड़ी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कोर्ट की छुट्टी खत्म होने के बाद होगी। याचिका में इस मामले की स्वतंत्र जांच और FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

पुलिस ने चंपत राय का बयान किया दर्ज

आपको जानकारी दें, कि आज राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की जांच कर रही पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का बयान दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर अनिल मिश्रा समेत ट्रस्ट के अन्य अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। अयोध्या पुलिस ने कहा कि चल रही जांच के तहत ट्रस्ट और मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान लिए जाएंगे।

राम के नाम पर सत्ता भी ले ली और दान भी लूट लिया : चंद्रशेखर आजाद

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। इस मुद्दे को लेकर सहारनपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर करोड़ों की लूट हुई है। वहीं, उत्तराखंड में पीड़ितों से मिलने से रोके जाने पर उन्होंने पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जुबानी हमला बोला।

इनकम टैक्स और सीबीआई को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए

दरअसल, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद शब्बीरपुर कांड की सुनवाई के सिलसिले में एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखे सवाल उठाए। चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम पर लोगों की आस्था से जुटाए गए धन में कथित लूट हुई है और इस पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप था कि यदि इतने बड़े स्तर पर नाम सामने आ रहे हैं तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसी एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले को उत्तराखंड पुलिस ने रोका

उत्तराखंड में टिहरी जिले के बहुचर्चित केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रविवार को हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने रोक दिया। आजाद टिहरी जनपद स्थित केतन के गांव पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात करने और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाने के लिए रवाना हुए थे। हरिद्वार पहुंचने पर पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी। काफिला रोके जाने की सूचना मिलते ही आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की बड़ी संख्या मौके पर जुट गई। समर्थकों ने पुलिस की इस पर नाराजगी जताई और सांसद को आगे जाने देने की मांग की। पुलिस ने संयम बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया।

पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर 1 जुलाई से हटेगी पाबंदी?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत में पेट्रोल और डीजल के बड़े खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई थीं, उसे देखते हुए भारत सरकार ने इसी महीने ईंधन की बिक्री पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थीं। अब स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इन प्रतिबंधों को खत्म करने का एलान कर दिया है।

सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर क्या नया आदेश जारी किया है?

सोमवार को सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस सरकारी आदेश के मुताबिक, ईंधन की खरीद और बिक्री को लेकर लागू की गई यह रोक 1 जुलाई से पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाली 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों और रिटेल स्टेशनों पर पहले की तरह ही सामान्य रूप से ईंधन उपलब्ध होने लगेगा।

ईंधन की बिक्री पर अचानक क्यों लगानी पड़ी थी पाबंदी?

दरअसल, यह पूरा मामला वैश्विक हालातों से जुड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर की आपूर्ति श्रृंखलाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विदेशी बाजार में सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से भारत के स्थानीय बाजारों में भी ईंधन की आपूर्ति को लेकर दबाव बन गया था। सरकार को यह आशंका थी कि अगर स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो देश के भीतर पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो सकती है। इसी घरेलू संकट को टालने के लिए सरकार ने इसी महीने ये प्रतिबंध लगाए थे।

1 जुलाई से इस फैसले का क्या असर दिखेगा?

सरकार के इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि ईंधन की सप्लाई से जुड़ी चिंताएं अब नियंत्रण में हैं। 1 जुलाई से व्यावसायिक खरीदारों के लिए रिटेल स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल खरीदने के रास्ते फिर से खुल जाएंगे और डीजल खरीद की दैनिक सीमा भी खत्म हो जाएगी। इससे कमर्शियल ट्रांसपोर्टरों और उद्योगों को अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिक और व्यावसायिक गतिविधियां पहले की तरह सुचारू रूप से चल सकेंगी।

इन प्रतिबंधों के दौरान किन नियमों का पालन करना पड़ रहा था?

सरकार की ओर से लगाई गई इस पाबंदी का सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए ईंधन खरीदने वालों पर पड़ा था। प्रतिबंधों के तहत, कमर्शियल खरीदारों को सीधे रिटेल स्टेशनों (पेट्रोल पंपों) से पेट्रोल और डीजल खरीदने से पूरी तरह रोक दिया गया था। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए सरकार ने डीजल की रोजाना खरीद पर भी एक सीमा तय कर दी थी। यानी कोई भी व्यावसायिक संस्था एक दिन में एक तय मात्रा से अधिक डीजल नहीं खरीद सकती थी।

32 साल का इंतजार हुआ खत्म

हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे पर बनी सहमति

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल प्रबंधन को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोनों राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे लंबे समय से लंबित जल संबंधी मुद्दों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को लेकर सहमति बनी।

■ बता दें कि इस समझौते के तहत वर्ष 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने पर सहमति बनी है। केंद्र सरकार का मानना है कि इस समझौते से न केवल दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग मजबूत होगा, बल्कि जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का आभार जताया।

हिंदमाता एंकरः शिशुओं के लिए पोषण मां का दूध होता है, विकास और मस्तिष्क के विकसित होने वाले सहायक तत्व होते हैं जैसे लंबी प्रोटीन श्रृंखला वाले फैटी एसिड...

स्तनपान से बच्चों को अतिसक्रियता के लक्षणों से बचाया जा सकता है : अध्ययन

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

अगर मां बच्चे को छह महीने की उम्र तक स्तनपान कराए तो उसमें तीन से आठ साल की उम्र में उभरने वाले एकाग्रता में कमी एवं अतिसक्रियता संबंधी एडीएचडी विकार के लक्षणों को कम किया जा सकता है। यह दावा नार्वे में करीब 36 हजार परिवारों पर किए अध्ययन के आधार पर किया गया है। अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर अथवा ध्यान अभाव एवं अतिसक्रियता (एडीएचडी) तंत्रिका से जुड़ी स्थिति है, जिसमें ध्यान न दे पाना और बेचैन व्यवहार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण आमतौर पर बचपन में ही रहते हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये वयस्क होने तक भी बने रह सकते हैं।

■ अध्ययन के मुताबिक शिशुओं के लिए पोषण का मुख्य स्रोत, मां का दूध होता है और इसमें विकास और मस्तिष्क के विकसित होने वाले सहायक तत्व होते हैं जैसे लंबी प्रोटीन श्रृंखला वाले फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एंटीबॉडी और फायदेमंद बैक्टीरिया। नॉर्वे के बर्गन विश्वविद्यालय सहित कई केंद्रों के अनुसंधानकर्ताओं ने अपने अध्ययन में यह समझने की कोशिश की कि स्तनपान बच्चे के दिमाग के विकास और प्रतिरोधक क्षमता पर को कैसे प्रभावित करता है। 'बायोलॉजिकल साइकियाट्री' नामक पत्रिका में प्रकाशित अनुसंधानपत्र के मुताबिक अध्ययन के दौरान इस बात का पता लगाने की कोशिश की गई कि शिशु को कितने महीनों तक केवल मां का दूध पिलाया गया और बच्चे में एडीएचडी के लक्षण विकसित होने के जोखिम से उसका क्या संबंध है।

■ बर्गन विश्वविद्यालय के बायोमेडिसिन विभाग में मनोवैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता और इस अनुसंधानपत्र की लेखिका डॉ. बेरिट स्क्रेटींग सोलबर्ग ने कहा कि हमने पाया कि बच्चे को जितने ज्यादा समय तक (छह महीने तक) सिर्फ मां का दूध पिलाया गया- तीन, पांच और आठ साल की उम्र में उनमें एडीएचडी के लक्षण उतने ही कम दिखे। उन्होंने बताया कि इस अध्ययन में शामिल नार्वे के परिवारों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। प्रश्नावली के जरिए, अनुसंधानकर्ताओं ने यह पता लगाया कि हर बच्चे को कितने महीनों तक केवल मां का दूध पिलाया गया।

■ अनुसंधान पत्र के लेखकों ने लिखा कि हर महीने पूरी तरह से स्तनपान करने वाले बच्चों में एडीएचडी के लक्षण कम सामने आए, जिससे ज्ञात होता है कि पूरी तरह से स्तनपान कराने का संबंध एडीएचडी के निम्न लक्षणों से है। उन्होंने कहा कि यह संबंध लड़कों और लड़कियों, दोनों में देखा गया। स्तनपान करने वालों पर प्रभाव तीन और पांच साल की उम्र में सबसे अधिक था और आठ साल की उम्र में थोड़ा कमजोर था। अनुसंधान टीम ने कहा कि स्तनपान से मिलने वाले सुरक्षात्मक लाभ इसकी अवधि और बारम्बारता से बढ़ते हैं, और छह महीने की उम्र तक केवल स्तनपान कराने पर ये सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक कारक आंशिक रूप से एडीएचडी की व्याख्या करते हैं।

■ अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि उदाहरण के लिए, अनुसंधान में सामने आया कि एडीएचडी के लक्षणों वाली माएं दूसरी माओं की तुलना में अपने बच्चों को कम स्तनपान कराती हैं और उनके बच्चों में भी एडीएचडी के लक्षण होने की आशंका अधिक हो सकती है। साथ ही, एडीएचडी के लक्षणों वाले बच्चों को स्तनपान कराना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सोलबर्ग ने कहा कि इससे बच्चों में कम स्तनपान और एडीएचडी के बढ़ते लक्षणों के बीच के संबंध को कुछ हद तक समझा जा सकता है। संभावित कारण-संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस अध्ययन में एडीएचडी के ज्ञात आनुवांशिकी जोखिम और सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों का भी विश्लेषण किया गया। इसके तहत एक ही परिवार के भीतर स्तनपान के अलग-अलग तरीकों की तुलना करते हुए भाई-बहनों पर उसके असर को देखा गया। सोलबर्ग ने कहा कि इन बदलावों के बाद भी, बाद में दिखने वाले एडीएचडी के लक्षणों पर केवल स्तनपान की अवधि का साफ लेकिन सीमित सुरक्षात्मक असर देखा गया। उन्होंने कहा कि चूंकि यह एक अवलोकन-आधारित अध्ययन है, इसलिए कारण-प्रभाव के संबंध के बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता एवं अधिक गहन अनुसंधान की जरूरत है।

कांग्रेस के पाप की वजह से बना बांग्लादेश, सत्ता लोभ का नतीजा: सीएम योगी

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश का बनना कांग्रेस पार्टी के किए गए पापों का नतीजा था। पाकिस्तान या बांग्लादेश के बनने की कोई खास जरूरत नहीं थी बल्कि, पाकिस्तान तो बस राजनीतिक सत्ता की लालच का एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा था। सीएम योगी ने कहा अगर लोग थोड़ा इंतजार करते, तो जिन्ना कुछ ही सालों में अपनी स्वाभाविक मौत मर जाते और पाकिस्तान कभी नहीं बनता। इसके बजाय, इस बंटवारे की वजह से लाखों लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनें छोड़नी पड़ीं और लाखों हिंदुओं का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। कांग्रेस ने देश की भारी कीमत पर अपनी राजनीति करना चुना। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर चलने वाली समाजवादी पार्टी के पास नागरिकों की परवाह करने का समय नहीं था। वे पूरी तरह से तुष्टिकरण की राजनीति में डूबे हुए थे। बंटवारे की भयावहता के बाद भी, उनका पूरा ध्यान एक खास अल्पसंख्यक समुदाय पर ही रहा, जबकि उन्होंने हिंदुओं, सिखों और जैनियों की बदहाली को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था।

हमारी सरकार में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही

सीएम योगी ने कहा कि आज, डबल-इंजन सरकार के मजबूत नेतृत्व में नागरिकता संशोधन कानून हकीकत बन गया है। ये बहुत अजीब बात है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उन्हीं नागरिकता प्रमाणपत्रों का विरोध किया था जो आज शरणार्थियों को बांटे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनके पास गरीबों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। इनके नेता दोपहर 12 बजे सोकर उठेंगे और शाम 5 बजे जिम जाएंगे। चार बार सरकार में रहने के बाद भी बबुआ को अगर समय मिलता, तब तो विकास होता! समाजवादी पार्टी के लोग जहां कट्टा (अवैध तमंचा) बनाते थे, वहीं आज हमारी सरकार में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही हैं। यूपी की जनता ने अब साइकिल को पूरी तरह पंचर कर दिया है। अगर साइकिल चलेगी तो दंगे कराएगी। आज के नए उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा; सब चंगा की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

जो चढ़ावा चोरी कर सकते वो सांसद-वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते: अखिलेश

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सपा के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते वो सांसद और वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते। सरकार को घेरते हुए सपा चीफ ने कहा कि चढ़ावा चोरी से बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कभी सांसदों की चोरी करती है तो कभी चढ़ावे की चोरी करती है। इनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश ने कहा कि राम जी की कृपा है बीजेपी डोनेशन के मामले में फस गई। तमाम लोग एक्सपोज हो गए हैं। बीजेपी भाईचारा खत्म करना चाहती है। सबसे बड़ा खतरा ये हिंदुस्तानियत को पैदा कर रहे हैं।

ये अयोध्या हारकर भी सबक नहीं सिख रहे

सपा चीफ ने कहा कि ये अयोध्या हारकर भी सबक नहीं सिख रहे हैं। राम जी ने जानकारी दी उनका चंदा चोरी हो रहा है। चंदा बोरों में भरकर कर्नाटक लेकर जाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी पीढ़ियों से जुडे. लोगों की पार्टी है। हम जल्दी टूटने वाले लोग नहीं है।

शिक्षा-परीक्षा ध्वस्त, पूरा सिस्टम बिक गया

उन्होंने कहा कि बीजेपी शिक्षकों से चारा इकट्ठा करवाती है। स्कूलों में आगंनवाड़ी में मायूसी है। विज्ञापन के लिए खजाना खुला है। सरकार में शिक्षा के लिए आधे से कम बजट दिया जा रहा है। नियुक्तियों में आरक्षण की धांधली हो रही है। युवाओं की मायूसी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े पैमाने पर बेटियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। शिक्षा और परीक्षा ध्वस्त हो गई है। पूरा सिस्टम बिक गया है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी खतरे में है। बीजेपी के एजेंडे में नौकरी नहीं है वरना यूपी में इतने पेपर लीक नहीं होते। अखिलेश ने कहा कि अगर सरकार की नियत साफ हो तो कभी पेपर लीक नहीं होगा।

शॉर्ट स्टोरी

बिहार के शिवहर में सिलेंडर ब्लास्ट, 8 घर जलकर राख, 6 झुलसे

हिंदमाता नेटवर्क @ शिवहर

बिहार में शिवहर जिले के तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के छपरा सिरहा टोला में सोमवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लगी और घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। इससे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। एसडीएम अविनाश कुणाल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। घटना में 8 घर जल गए, जिससे लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक घर में अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। कुछ ही देर में आग ने आसपास के कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों को घरों से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि, तब तक 8 घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन, नकदी समेत लाखों रुपये की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी थी। घटना में गंभीर रूप से झुलसे सभी 6 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

खान सर की बढ़ेंगी मुश्किलें, बॉडीगार्ड का हथियार अवैध

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

बिहार की राजधानी पटना में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदू कोचिंग के बीच हुए विवाद में दर्ज मामले में नई केस डायरी सामने आने के बाद खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस की अपडेटेड केस डायरी में फायरिंग करने वाले दोनों बॉडीगार्ड के हथियारों और लाइसेंस से जुड़े अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है फैजल खान (खान सर) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस जांच के अनुसार, 2 जून को हुई फायरिंग के दौरान खान के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह ने जिस हथियार से गोली चलाई थी। उसका लाइसेंस केवल यूपी तक ही वैध था। तालेबर सिंह उत्तर प्रदेश का निवासी है, लेकिन बिहार में हथियार लेकर ड्यूटी करने के लिए उसके पास आवश्यक वैध अनुमति नहीं थी। साथ ही स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। ऐसे में बिहार में उसका हथियार अवैध श्रेणी में माना जा रहा है। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप, जो उत्तर प्रदेश का निवासी है। उसके पिता की हत्या के बाद उसे आत्मरक्षा के लिए देशभर में वैध हथियार का लाइसेंस मिला था। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने इस लाइसेंस का इस्तेमाल निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ व्यावसायिक लाभ के लिए किया, जो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन माना जा रहा है। पुलिस ने अपडेट केस डायरी कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब इसकी के आधार पर कल कोर्ट में फैजल खान, दोनों बॉडीगार्ड और उनके तीन स्टाफ कन्हैया, अजीत और अंकित पांडेय की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। दोनों बॉडीगार्ड न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि कोर्ट ने 30 जून तक फैजल खान और तीनों स्टाफ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

अपराधियों को हर हाल में नेपाल जाना ही होगा-सम्राट चौधरी

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है, बिहार में कचरा भगाने का अभियान जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि अपराधियों के पास नेपाल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो अपराधी हैं उन्हें हर हाल में नेपाल जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि राज्य से अपराध और अपराधियों का सफाया करने का अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रदेशव्यापी पंचायत विकास शिविर का शुभारंभ करने के लिए बिहार के मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं और साथ ही सरकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले 9 हजार अधिकारियों को नोटिस भेजा जा चुका है। अगर कोई अधिकारी जनता की समस्या का समाधान करने में आनाकानी करता है, तो उसपर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है, 31वें दिन उसे सीधे निलंबित कर दिया जाएगा। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2026 के बाद किसी भी सरकारी अस्पताल से मरीजों को बिना उचित कारण के रेफर नहीं किया जाएगा और अगर कोई अधिकारी ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़ना है। इसके अलावा हर प्रखंड को पथ निर्माण विभाग के सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1.81 करोड़ महिलाएं जीविका समूहों सेजुड़कर सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

रेलवे की जमीन या व्यापारियों का हक? 40 दुकानों पर बेदखली का नोटिस

250 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

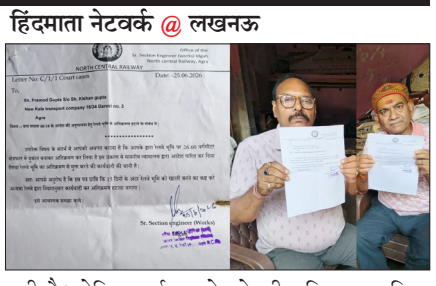

देशभर में यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे लगातार अपने नेटवर्क और संसाधनों का विस्तार कर रही है। लेकिन कई बार रेलवे की भूमि पर स्वामित्व को लेकर ऐसे विवाद सामने आ जाते हैं, जिनमें वर्षों से बसे लोगों और व्यापारियों की आजीविका दांव पर लग जाती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सामने आया है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर से सटी करीब 36 वर्ग मीटर भूमि को अपनी संपत्ति बताते हुए वहां वर्षों से व्यापार कर रहे 40 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर भूमि खाली करें, अन्यथा रेलवे प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

आजादी से पहले का बाजार, चार पीढ़ियों का कारोबार

जिस बाजार को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हुई है, उसे व्यापारी आजादी से पहले का बाजार बताते हैं। कई दुकानदारों का कहना है कि उनके परिवार की चार पीढ़ियां इसी स्थान पर व्यापार करती आ रही हैं। ऐसे में अचानक नोटिस मिलने से उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

व्यापारियों का दावा– यह रेलवे नहीं, छावनी बोर्ड की जमीन

प्रभावित व्यापारियों का कहना है कि संबंधित भूमि रेलवे की नहीं बल्कि आगरा छावनी बोर्ड की है। उनका दावा है कि उनके पास छावनी बोर्ड द्वारा जारी रसीदें मौजूद हैं, जिनके आधार पर वे वर्षों से शुल्क जमा करते रहे हैं। कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि उनके पास संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री भी उपलब्ध है। ऐसे में रेलवे द्वारा भूमि पर अपना दावा जताते हुए नोटिस जारी करना उनकी समझ से परे है।

250 परिवारों की आजीविका पर संकट

व्यापारियों ने भावुक होकर कहा कि यह केवल 40 दुकानों का मामला नहीं है। प्रत्येक दुकान से कई कर्मचारी जुड़े हुए हैं। यदि दुकानों को हटाया गया तो करीब 200 से 250 परिवार, यानी लगभग 4 से 5 हजार लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। उनका स्पष्ट कहना था कि संबंधित भूमि रेलवे की है और न्यायालय के माध्यम से रेलवे अपने अधिकार स्थापित कर चुका है। अधिकारियों के अनुसार अब व्यापारियों को हर हाल में भूमि खाली करनी होगी और रेलवे अपनी संपत्ति वापस लेकर ही रहेगा।

शामली धर्मांतरण केस में नया ट्विस्ट, आयुष मलिक की 'घर वापसी'

मोहम्मद अली से फिर बना हिंदू

हिंदमाता नेटवर्क @ शामली

उत्तर प्रदेश के शामली में आयुष मलिक के धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। धर्म परिवर्तन के बाद मोहम्मद अली नाम से पहचाने जाने वाले आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। उनकी घर वापसी के बाद उनका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया था, लेकिन परिवार वालों की परेशानी देखते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना रहे हैं। आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक का दावा है कि उनके बेटे ने फिर से सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैशी नामक मुस्लिम लड़की और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने साजिश के तहत आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया था। करोड़ों रुपए की जायदाद हड़पने के मकसद से आयुष को मोहम्मद अली बनाया और परिवार से दूर करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह केस देवराज मलिक की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका बेटा आयुष मलिक मेडिकल स्टोर को संभालने में मदद करता था। चांदनी कुरैशी के संपर्क में आने के बाद बदल गया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आयुष को रिश्ते में फंसाकर धीरे-धीरे धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया गया। आयुष और चांदनी की पहली मुलाकात साल 2018 में एक हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय आयुष पैर की चोट का इलाज कराने गया था। इसके बाद दोनों के बीच रिश्ता बन गया। इसके बाद चांदनी के परिवार के लोग उसे प्रभावित करने लगे। शिकायत के मुताबिक, साल 2023 में आयुष को दिल्ली ले जाया गया। वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उसका नाम मोहम्मद अली रख दिया गया। दिल्ली में एक निकाह समारोह हुआ था। हालांकि, जांच के दौरान कोई मैरिज सर्टिफिकेट बरामद नहीं हुआ था। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद आयुष ने दाढ़ी बढ़ाने, पांच बार नमाज पढ़ने और कपड़े बदलने जैसे इस्लामी रीति-रिवाज अपनाए। पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के साथ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत भी केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार किए गए चांदनी कुरैशी और इस्लाम कुरैशी के अलावा FIR में परिवार के कई अन्य सदस्यों और दो अज्ञात मौलवियों का भी नाम शामिल है। फिलहाल आयुष मलिक की घर वापसी के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

'मम्मी-पापा माफ करना..', बीएचयू के डॉक्टर ने आईवी ड्रिप लगाकर की आत्महत्या

हिंदमाता नेटवर्क @ वाराणसी

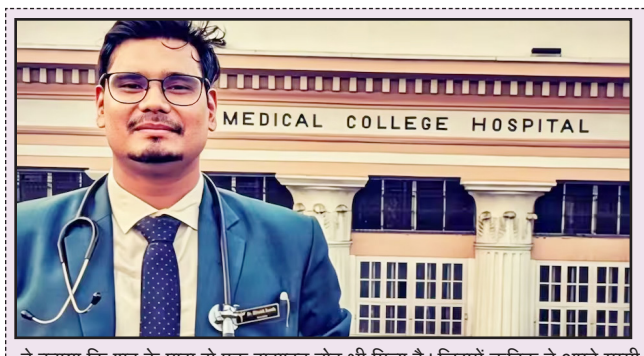

वाराणसी में आत्महत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक जूनियर डॉक्टर ने खुद को ही ड्रिप के सहारे दवा चढ़ाकर मौत को गले लगा लिया। घटना आईएमएस-बीएचयू के सुश्रुत हॉस्टल की है। यहां 26 साल के पश्चिम बंगाल हुगली के रहने वाले ऋत्विक कुंदू ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें एक लड़की से प्यार करने का जिक्र भी किया गया है। दरअसल ऋतिक वाराणसी के आईएमएस-बीएचयू में एनेस्थीसिया विभाग में जूनियर डॉक्टर थे। काफी देर तक जब वह क्लास में या ड्यूटी पर नहीं दिखाई पड़े तो उनकी खोजबीन शुरू हुई। लोग उनके सुश्रुत हॉस्टल के कमरा नंबर 361 पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। साथियों ने इसकी सूचना तुरंत बीएचयू प्रशासन को दी। जिसके बाद हॉस्टल का ताला तोड़ा गया तो ऋतिक अंदर अपने बेड पर पड़े थे और एक ड्रिप उनको लगी हुई थी।

सुसाइड नोट में इन बातों का है जिक्र

पहली दफा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ड्रिप के सहारे ही एनेस्थीसिया की दवा लेने के चलते ओवरडोज की वजह से ऋत्विक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने बताया कि शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें ऋतिक ने अपने मम्मी-पापा से माफी मांगी है और कहां है कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि जिंदगी बहुत शॉर्ट है। जिसका पता बाहर से नहीं चल सका, लेकिन यहां आकर पता चला कि जीवन में बहुत संघर्ष है। उसने यह भी लिखा कि वह अपनी इच्छा से जान दे रहा है। इसके लिए किसी को परेशान ना किया जाए। खासकर उस लड़की को, जो उससे बहुत प्यार करती है। उसके लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों परिजनों मैं जा रहा हूं अलविदा दुनिया..

शताब्दी एक्सप्रेस में फर्जी टीटी बनकर घूम रहा था युवक

कानपुर आरपीएफ की सतर्कता से दबोचा गया

हिंदमाता नेटवर्क @ कानपुर

कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली जा रही गाड़ी संख्या 12033 शताब्दी एक्सप्रेस में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल शताब्दी एक्सप्रेस में एक व्यक्ति नकली टीटी बनकर घूम रहा था। हालांकि यह नकली टीटी आरपीएफ की सतर्कता से पकड़ा गया। हैरान की बात तो यह रही है कि आरोपी के पास फर्जी पहचान पत्र भी था जिसके सहारे वह खुद को रेलवे का टीटी बताकर यात्रियों के बीच घूम रहा था।

हाव-भाव पर हुआ संदेह

जानकारी के मुताबिक आरपीएफ पोस्ट कानपुर सेंट्रल के हेड कांस्टेबल लीलाधर और कांस्टेबल मनोज कुमार-2 ट्रेन में अनुरक्षण ड्यूटी पर तैनात थे। यात्रा के दौरान स्टेशन से एक व्यक्ति कोच सी-11 में चढ़ा और स्वयं को टीटी बताने लगा। लेकिन उसके हाव-भाव पर संदेह होने पर आरपीएफ कर्मियों को संदेह हुआ जिसके बाद रेलवे पुलिस फोर्स के कांस्टेबल टीएस जितेंद्र सिंह यादव और कोच टीटी अनुज कुमार ने मिलकर उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह कोई सही जवाब नही दे पाया।

टीटी के नाम पर बनवाया फर्जी आई-कार्ड

हालांकि शुरूआती पूछताछ में उसने खुद को नॉर्दर्न रेलवे में टीटी के पद पर कार्यरत बताया था। लेकिन जब सख्ती बरती गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि वह रेलवे कर्मचारी नहीं है। उसने फर्जी आई-कार्ड बनवाकर टीटी बनकर यात्रा करने की बात भी कबूल की। आरोपी ने अपना असली नाम दुर्वेश कुमार पुत्र भोजराज निवासी ग्राम नगला, जनपद एटा बताया। जानकारी के मुताबिक उसकी असली पहचान उजागर होने के बाद आरपीएफ ने आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गाजियाबाद स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया।

सीपू सिंह हत्याकांड: बवाल में 49 नामजद और 1000 अज्ञात पर दर्ज मुकदमे वापस

13 साल पहले हुई थी घटना

हिंदमाता नेटवर्क @ आजमगढ़

सगड़ी से सपा के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड के बाद हुए बवाल और आगजनी के मामले में 49 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे शासन ने वापस ले लिए हैं। अभियोजन विभाग के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने शनिवार को इन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी। बसपा की पूर्व विधायक व पत्नी वंदना सिंह ने इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताया है। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। पहले में 49 लोगों को नामजद और एक हजार अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस अब तक इस मामले में 42 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। दूसरे मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सर्वेश सिंह उर्फ सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को जीयनपुर स्थित उनके आवास पर हुई थी। मामले में माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सीपू सिंह की हत्या के बाद जीयनपुर में भारी बवाल हुआ था। आक्रोशित जनता और पुलिस आमने-सामने थी। ग्रामीणों ने पुलिस के हथियार लूट लिए थे। उनके वाहनों को जला दिया था।

बोलीं पूर्व विधायक

पूर्व विधायक वंदना सिंह ने बताया कि मेरे पति की 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की तरफ से 49 लोगों नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। साल 2017 में जब मैं विधायक बनी तबसे इनके हक की लड़ाई लड़ रही थी। संघर्ष के बाद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री योगी के प्रयास के बाद सभी मुकदमे वापस लिए गए हैं।

हिंदमाता एंकर: शनिवार को अर्जुन यादव, टीना यादव और सांसद प्रिया सरोज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चकों ने विधि-विधान से उनका पूजन संपन्न कराया

काशी पहुंचे अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, बनारसी मिठाई का भी लिया स्वाद

हिंदमाता संवाददाता @ वाराणसी

उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर धर्मनगरी काशी से सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पुत्र अर्जुन यादव और पुत्री टीना यादव ने शनिवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उनके साथ सांसद प्रिया सरोज भी मौजूद रहीं। दर्शन-पूजन के बाद उन्होंने बनारस की मशहूर मिठाई का स्वाद भी चखा।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से संपन्न हुई पूजा

शनिवार को अर्जुन यादव, टीना यादव और सांसद प्रिया सरोज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से उनका पूजन संपन्न कराया। तीनों ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में माथा टेककर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।

बनारसी मीठे का लिया स्वाद

पूजा अर्चना के बाद अर्जुन यादव और टीना यादव मंदिर से बाहर निकले और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष यादव के साथ शहर की एक प्रसिद्ध मिष्ठान की दुकान पहुंचे। अखिलेश यादव के बच्चों को जौनपुर के मछली शहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने बनारस घुमाया और दर्शन व पूजा- अर्चना भी करवाया। इस दौरान अखिलेश के दोनों बच्चे संकट मोचन मंदिर भी गए और वहां विधि विधान से दर्शन पूजन करके वे सीधे गंगा घाट पहुंचे।

एक घंटे तक गंगा की लहरों पर देखी बनारस की खूबसूरती

जहां नाव पर सवार होकर उन्होंने लगभग एक घंटे तक गंगा की लहरों पर बनारस की खूबसूरती देखी और उसका आनंद लिया। वहां दोनों ने बनारसी मीठे का स्वाद लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। उनकी एक झलक पाने के लिए समर्थकों और राहगीरों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। इस दौरान टीना यादव नाव पर रील बनाती और सेल्फी लेती भी दिखाई दी।

समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु यादव ने दी जानकारी

उनके इस दौरे का बारें में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु यादव ने बताया कि रविवार की शाम अखिलेश यादव के दोनों बच्चे वाराणसी आए थे। जहां वे एक होटल में रुके। उनके साथ सांसद प्रिया सरोज भी रही। उन्होंने ही दोनों को रिसीव किया और इन्हें लेकर सीधे विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। धार्मिक आस्था और बनारस की संस्कृति से जुड़ी इस यात्रा की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस दौरे को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि यह दौरा पूरी तरह धार्मिक और निजी बताया जा रहा है।

यूरोप में मौत बनकर बरसी गर्मी!

फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत, दशकों के रिकॉर्ड टूटे

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

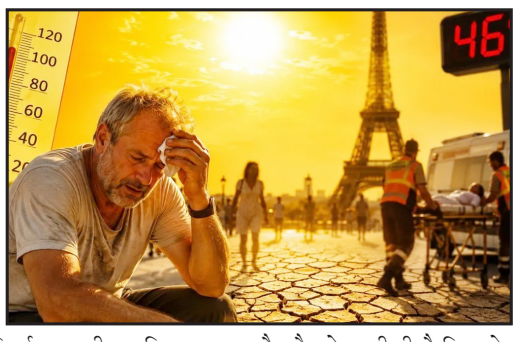

पूरा यूरोप इस समय भीषण गर्मी और लू की अभूतपूर्व लहर से जूझ रहा है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने रविवार को चौंकाने वाले आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह में गर्मी के कारण देश में लगभग 1,000 से अधिक मौतें हुई हैं। विशेषज्ञों ने इस स्थिति को जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम बताया है और चेतावनी दी है कि यूरोप अब दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है। पूरा यूरोप इस समय भीषण गर्मी और लू की अभूतपूर्व लहर से जूझ रहा है। फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने रविवार को चौंकाने वाले आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह में गर्मी के कारण देश में लगभग 1,000 से अधिक मौतें हुई हैं। विशेषज्ञों ने इस स्थिति को जलवायु परिवर्तन का सीधा परिणाम बताया है और चेतावनी दी है कि यूरोप अब दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन चुका है।

फ्रांस में मौतों का भयावह आंकड़ा

फ्रांस में पिछले हफ्ते तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, अकेले बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मौतों की संख्या में भारी उछाल देखा गया। सामान्य दिनों में फ्रांस में प्रतिदिन मौतों का औसत 900 से 1,000 के बीच रहता है, लेकिन गर्मी के चरम पर यह आंकड़ा प्रति दिन 1,400 को पार कर गया। एजेंसी ने पुष्टि की है कि इन तीन दिनों में कम से कम 1,000 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मरने वालों में 85 प्रतिशत लोग 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे।

दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होता महाद्वीप

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यूरोप वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। वर्तमान में लगभग 15 करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी की स्थिति में रह रहे हैं, जिससे स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और बिजली ग्रिड ठप हो रहे हैं। टेड्रोस ने गर्मी को एक साइलेंट किलर करार दिया और यूरोपीय देशों से तत्काल कार्य योजना लागू करने की अपील की है। गर्मी की यह लहर अब धीरे-धीरे पूर्वी यूरोप की ओर बढ़ रही है। जर्मनी में लगातार तीसरे दिन तापमान का नया रिकॉर्ड बना, जहां नेइस्सेमुंडे में पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

एक तरफ ईरान में खामेनेई का जनाजा, दूसरी ओर अमेरिका में आजादी का जश्न

चार जुलाई पर दुनिया की नजर

हिंदमाता नेटवर्क @ तेहरान

जुलाई की शुरूआत में दुनियाभर में बड़ी हलचल देखी जा सकती है। अमेरिका एक तरफ जहां बड़े जोर-शोर से चार जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। वहीं, ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को अंतिम विदाई दे रहा होगा। इन दोनों ही घटनाओं पर दुनियाभर की नजरें होंगी। चार जुलाई को अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ होगी। ऐसे में अमेरिका में हफ्तेभर तक कार्यक्रम किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चार जुलाई को नेशनल मॉल में होने वाले दुनिया के सबसे शानदार आयोजन को संबोधित करेंगे। वहीं, ईरान तीन से पांच जुलाई तक आयुतल्लाह अली खामेनई को अंतिम विदाई दे रहा है। उनके जनाजे में करोड़ों लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा जनसैलाब होगा। इससे पहले 1989 में ईरान के पहले सर्वोच्च नेता रुहोल्लाह खुमैनी के जनाजे में तकरीबन एक करोड़ लोग जुटे थे। उनके उत्तराधिकारी अली खामेनेई पश्चिम एशिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रमुख थे। इस साल 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में उनकी हत्या कर दी गई थी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर 13,000 से अधिक हवाई हमले किए, जिसके कारण आयतुल्लाह को अंतिम विदाई देना बेहद जोखिम भरा हो गया था। हालांकि आठ अप्रैल से अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम लागू है।

45 साल भी अमेरिका-ईरान आमने-सामने

ट्रंप के नेतृत्व में चला पांच सप्ताह का युद्ध ईरान को काफी कमजोर जरूर कर गया, लेकिन अमेरिका अपने अमेरिका अपना प्रमुख लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, ना उसने उच्च संवर्धित यूरेनियम छोड़ा, ना परमाणु कार्यक्रम समाप्त किया, ना क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों का समर्थन खत्म किया और ना ही अपनी बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना छोड़ी। इसे विपरीत, ईरान ने होर्मुज को अवरुद्ध कर दिया, जहां से दुनिया की लगभग 25 फीसदी तेल की सप्लाई होती है। ईरान की बात करें तो यहां सत्ता पर कट्टरपंथी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स काउंसिल का प्रभाव और मजबूत हो गया है। उनके लिए खामेनेई की अंतिम विदाई दुनिया को कई संदेश देने का अवसर है। अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि खामेनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा या फिर तेहरान स्थित करीब दो अरब डॉलर की लागत से बने रुहोल्लाह खुमैनी मकबरे में लेकिन यह तय माना जा रहा है कि पूरा आयोजन राजनीतिक संदेश देने के उद्देश्य से किया जाएगा।

ईरान से पीएम मोदी को न्योता, लेकिन खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत ने क्यों भेजा बिहार का यह बड़ा चेहरा?

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत शामित होगा। इसकी पुष्टि हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण आया था। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, खबर आ रही है कि भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ईरान में खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 4 और 5 जुलाई को तेहरान में होगा।

4 महीने बाद हो रहा होगा अंतिम संस्कार

खामेनेई की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करीब चार महीने बाद, जुलाई को तेहरान में होगा। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन के बाद तेहरान में सार्वजनिक जुलूस निकाला जाएगा।

अमेरिकी हमले में हो गई थी मौत

बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की इजरायली और अमेरिकी हमलों में 28 फरवरी मौत हो गई थी। युद्ध के मद्देनजर उस समय खामेनेई का अंतिम संस्कार टाल दिया गया था। पिछले दिनों ही अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम पर सहमति बन गई है। इसके बाद अब अगले महीने की 4 और 5 जुलाई को खामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह का कार्यक्रम रखा गया है।

पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे?

ईरान की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रण मिलने के बाद कूटनीतिक गलियारों में कयास लगने लगे थे कि क्या पीएम ईरान जाएंगे? लेकिन अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान पहले से तय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के कारण तेहरान नहीं जा पाएंगे। अगले महीने पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दौरे पर रहेंगे। इसका शेड्यूल पहले से ही तय है।

कराची हमले का पाकिस्तान ने लिया बदला!

आधी रात अफगानिस्तान सीमा पर भीषण सैन्य कार्रवाई, 29 की मौत

हिंदमाता नेटवर्क @ कराची

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान की ओर से रविवार देर रात अफगानिस्तान से लगी सीमा पर एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई में अब तक कम से कम 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान सरकार ने इसे हालिया आतंकी हमलों का करारा जवाब बताया है।

खुफिया जानकारी पर आधारित था ऑपरेशन

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने स्थानीय मीडिया के हवाले से पुष्टि की है कि यह हमला पूरी तरह से सुनियोजित और खुफिया जानकारी पर आधारित था। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने सीमावर्ती इलाकों में उन ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। यह ऑपरेशन रविवार की देर रात शुरू हुआ और इसने सीमा के दोनों तरफ हड़कंप मचा दिया है। सूचना मंत्री तरार के अनुसार, यह सख्त कार्रवाई हाल के दिनों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हुई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर की गई है। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची जैसे शहरों में निर्दोष नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि इन हमलों की साजिश सीमा पार से रची जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया।

विश्व युद्ध का खतरा टला? अमेरिका और ईरान हमले रोकने पर सहमत

कतर में होगी होर्मुज पर महाबैठक

हिंदमाता नेटवर्क @ वॉशिंगटन

पश्चिम एशिया में मंडरा रहे युद्ध के बादलों के बीच एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे अमेरिका और ईरान अब आपसी सैन्य हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था और दुनिया एक बड़े सैन्य टकराव की आशंका से सहमी हुई थी।

सीजफायर के बाद भी जारी थे हमले

अमेरिका और ईरान के बीच अभी हाल ही में सीजफायर लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पिछले 24 घंटों के भीतर ही दोनों ओर से एक-दूसरे के ठिकानों पर फिर से हमले किए गए, जिससे इस समझौते के टूटने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, अब एक्सियोस की एक रिपोर्ट में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि दोनों पक्ष फिलहाल काइनेटिक एक्टिविटी यानी सैन्य हमलों और आक्रामक कार्रवाइयों को पूरी तरह से रोकने के लिए राजी हो गए हैं। तनाव को कम करने की दिशा में अगला बड़ा कदम कतर की राजधानी दोहा में उठाया जाएगा। मंगलवार को दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल एक मेज पर बैठेंगे ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जारी विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सके।

ट्रंप की चेतावनी

इस समझौते से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो वे युद्ध को दोबारा शुरू कर काम पूरा कर देंगे और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वहीं, दूसरी ओर ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया था कि यदि अमेरिका ने सीजफायर का उल्लंघन किया, तो भविष्य की सभी कूटनीतिक बातचीत और रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे।

होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर राहत

समझौते का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि बातचीत की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के हो सकेगी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, दोनों पक्ष फिलहाल पीछे हटने को तैयार हैं ताकि कतर में होने वाली बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाया जा सके।

चीन में तख्तापलट का डर? एयरफोर्स से आर्मी तक के टॉप अफसरों की छुट्टी

हिंदमाता नेटवर्क @ बीजिंग

चीन से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। यहां सरकार ने एक साथ कई बड़े सैन्य अधिकारियों और नेताओं को उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार को हुई है और इसकी जानकारी सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने दी है। इस लिस्ट में पूर्व वित्तीय नियामक प्रमुख ली युंझे और पोलित ब्यूरो के सदस्य मा शिंगरुई का नाम भी शामिल है, जो हाल ही में जांच के दायरे में आए थे। खास बात यह है कि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि इन सभी को आखिर किस वजह से हटाया गया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि देश की टॉप विधायी संस्था नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने छह सैन्य सांसदों के साथ-साथ दो बड़े नेताओं के पदों को खत्म कर दिया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सबसे बड़ी कानून बनाने वाली संस्था है, इसलिए इसमें होने वाले बदलाव बहुत अहम माने जाते हैं। हटाए गए नेताओं में पूर्व वित्तीय नियामक प्रमुख ली युंझे और हाल ही में जांच का सामना कर रहे पोलित ब्यूरो सदस्य मा शिंगरुई का नाम शामिल है। यह जानकारी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से जारी एक नोटिस में दी गई है। इस नोटिस में किसी को भी हटाने की वजह नहीं बताई गई है। इसके अलावा चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री से जब इस मामले पर जवाब मांगा गया तो वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बता दें कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी

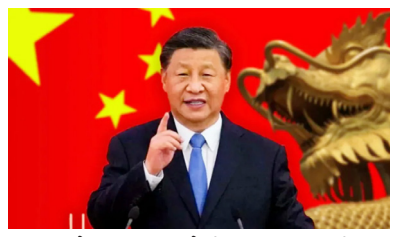

जिनपिंग के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का ही एक हिस्सा है। यह अभियान पिछले कई सालों से चल रहा है और इसमें कई बड़े अधिकारियों और टॉप जनरलों की जांच हुई है, उन्हें हटाया गया है और पद से भी बेदखल किया गया है। यह ताजा कार्रवाई इस मामले में सबसे नई और बड़ी कड़ी मानी जा रही है। जिन सैन्य सांसदों को हटाया गया है उनमें जनरल शू श्युछियांग का नाम सबसे ऊपर है। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के इक्विपमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रमुख थे। यह विभाग चीन की सेना यानी पीएलए के लिए हथियार और उपकरण बनाने, खरीदने और उनकी टेस्टिंग का काम देखता है। इसके साथ ही शू श्युछियांग साल 2022 से चीन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के कमांडर-इन-चीफ भी थे, यानी उनका पद बहुत बड़ा और अहम माना जाता था। इनके अलावा जनरल ली फेंगबियाओ को भी हटाया गया है, जो पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड में पॉलिटिकल कमिश्नर के पद पर थे।

हिंदमाता एंकर

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हो गए खफा, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे को लेकर विवाद गरमाया

हमारे पीएम भीख का कटोरा लेकर चीन नहीं गए..', सवाल पर भड़के बांग्लादेशी विदेश मंत्री, कहा- ऐसे सवाल से शर्मिंदगी होती है

हिंदमाता नेटवर्क @ ढाका

अक्सर 'भीख का कटोरा' की चर्चा पाकिस्तान के संदर्भ में होती है, पाकिस्तान अमूमन दुनिया भर से मदद मांगने के लिए जाता रहता है। लेकिन इस बार ये चर्चा बांग्लादेश को लेकर हो गई। चर्चा भी ऐसी हुई कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री बुरा मान गए। दरअसल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे पर एक अजीब विवाद पैदा हो गया है। मीडिया की ओर से बार बार चीन से मिलने वाली आर्थिक मदद पर सवाल पूछने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने चिढ़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन कोई भीख का कटोरा लेकर नहीं गए हैं। वे वहां दोनों देशों के बीच संबंधों की दशा-दिशा तय करने गए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री पीएम के दौरे पर ढाका में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का नेता 'भीख का कटोरा' लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में शामिल नहीं होते हैं। बीजिंग से मिलने वाली सीधी प्रोजेक्ट सहायता के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा, "आपने नकद राशि मिलने की बात की। भाइयों, कृपया ऐसे सवाल न पूछें; इससे हमें बहुत शर्मिंदगी होती है। खलीलुर ने ये बातें शनिवार को विदेश मंत्रालय में आयोजित एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहीं, जो प्रधानमंत्री की हालिया मलेशिया और चीन यात्राओं के संबंध में थी। बता दें कि बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में भारी जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार के मुखिया तारिक अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकले और 21 जून को मलेशिया पहुंचे।

थोड़ी आत्म-सम्मान बनाए रखें

चीन की ओर से मिलने वाली सीधी परियोजना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने पत्रकारों से कहा कि आपने नकद राशि मिलने का जिक्र किया। भाइयों, कृपया आपलोग ऐसा कोई भी सवाल न पूछें; यह मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। खलीलुर रहमान ने आगे कहा कि बांग्लादेश के पीएम दोनों देशों के बीच रिश्तों की दिशा और दायरा तय करने लिए चीन गए थे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का कोई भी प्रमुख दूसरे देश के नेता के साथ कागज और पेंसिल लेकर नहीं बैठता और न ही वे कोई भीख का कटोरा लेकर जाते है। कृपया थोड़ी आत्म-सम्मान बनाए रखें।

दोनों देशों के बीच 17 समझौते हुए

शनिवार को विदेश मंत्रालय में एक प्रेस ब्रिफिंग के दौरान बंग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने यह बयान दिया है, जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया मलेशिया और चीन यात्राओं को लेकर था। गौरतलब है कि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हुए चुनावों में भारी जीत के बाद बीएनपी की सरकार के मुखिया तारिक अपनी पहली विदेश यात्रा पर निकले और 21 जून को मलेशिया पहुंचे। अगले दिन वह उत्तर-पूर्वी चीन के शहर डालियान का दौरा किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होने के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान तीन दिन की यात्रा शुरू करने के लिए बुधवार को बीजिंग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रीमियर ली कियांग के साथ हाई-लेवल द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच कुल 17 MoU पर हस्ताक्षर हुए।

बिजनेस वर्ल्ड

ट्रांसरेल लाइटिंग को इंटरनेशनल बाजार मिले 459 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (टीएंडडी) क्षेत्र की अग्रणी ईपीसी कंपनियों में से एक है, ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुख्य रूप से ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय में लगभग 459 करोड़ रुपए के नए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर हासिल किए हैं। इन नए ऑर्डर्स में मुख्य रूप से मेना क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए ईपीसी परियोजनाएं शामिल हैं, जो कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बुक को और मजबूत करती हैं। ये जीत वैश्विक बाजारों में बड़े ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में ट्रांसरेल की स्थापित क्षमताओं को और मजबूत करती हैं। इसके साथ ही, ट्रांसरेल को इस वर्ष 1,034 करोड़ रुपये तक के नए ऑर्डर मिल चुके हैं, इसके अलावा लगभग 400 करोड़ रुपये की एक एल1 स्थिति भी बनी हुई है। कंपनी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक मजबूत बिडिंग पाइपलाइन का लाभ मिलना जारी है। एक मजबूत ऑर्डर बुक और बेहतरीन बिडिंग पाइपलाइन कंपनी के दीर्घकालिक विकास दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान करती है। कंपनी के एमडी एवं सीईओ श्री रणदीप नारंग ने कहा, इन नए ऑर्डर्स से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी स्थिति और मजबूत होगी। यह दिखाता है कि हमारे ग्राहकों को हमारी इंजीनियरिंग और काम पूरा करने की क्षमता पर कितना भरोसा है। मजबूत ऑर्डर बुक और अच्छी बिडिंग पाइपलाइन के साथ, हम अपनी तरक्की की रफ़्तार बनाए रखने की बेहतर स्थिति में हैं। हम अपने काम को बेहतरीन और परिचालन उत्कृष्टता के साथ पूरा करना जारी रखेंगे, जिससे कंपनी लगातार मुनाफे के साथ आगे बढ़ती रहे।

मई में 5.1% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन, इन सेक्टर्स में दिखा सबसे ज्यादा दम

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। देश के औद्योगिक उत्पादन में मई महीने के दौरान शानदार 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल में यह आंकड़ा 4.9 प्रतिशत पर था। कारखानों में बढ़ती गतिविधियां और बिजली उत्पादन में आए जोरदार उछाल ने इस विकास को नई ऊर्जा दी है। फैक्ट्रियों में बढ़ता उत्पादन इस बात का संकेत है कि बाजार में मांग पूरी तरह से बरकरार है। उत्पादन में यह तेजी अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमाती है, जिससे आने वाले समय में रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होते हैं। आईआईपी इंडेक्स में 76 फीसदी का भारी-भरकम वजन रखने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थव्यवस्था की रीढ़ साबित हो रहा है। मई में इस सेक्टर ने 5.5 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सबसे ज्यादा 20.8 प्रतिशत का उछाल इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्माण में देखा गया है। इसके अलावा, मेटल से बने उत्पादों में 15.5 प्रतिशत, मोटर वाहनों में 14.5 प्रतिशत तथा कंप्यूटर-इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 11.4 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। भारी मशीनरी और पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में हो रहा यह विस्तार इस बात की गवाही देता है कि देश में निवेश की मांग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च लगातार ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। मई महीने की तपती गर्मी ने भी औद्योगिक आंकड़ों को एक बड़ा सहारा दिया। बिजली और गैस सप्लाई इस महीने ओवरऑल ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर बनकर उभरे, जिसमें 9.9 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि देखी गई। अगर सिर्फ बिजली उत्पादन की बात करें तो यह 11.1 प्रतिशत तक बढ़ गया। दरअसल, गर्मियों में एसी, कूलर तथा अन्य उपकरणों के इस्तेमाल से बिजली की मांग अपने चरम पर होती है, जिसका सीधा असर इन शानदार आंकड़ों के रूप में सामने आया है। निवेश से जुड़े कैपिटल गुड्स (मशीनरी आदि) के उत्पादन में 12.9 प्रतिशत का तगड़ा उछाल आया है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 9.5 प्रतिशत था। इसी तरह, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (जैसे टीवी, फ्रिज, गाड़ियां) में 7.2 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह मजबूती दिखाती है कि शहरों में लोगों के हाथ में पैसा है और वे अपनी पसंद की चीजों पर खुलकर खर्च कर रहे हैं। हालांकि, रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजों (कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स) की ग्रोथ 3.6 प्रतिशत रही।

बर्बादी की कगार पर वेनेजुएला, 6.7 बिलियन डॉलर का सीधा नुकसान

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

सालों से वेनेजुएला एक के बाद एक संकट का सामना कर रहा है। देश को बहुत ज्यादा महंगाई, बार-बार बिजली कटौती, लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और लगभग ठप हो चुकी इकोनॉमी का सामना करना पड़ा। 2026 में हालात आखिरकार थोड़े बेहतर होने लगे थे। तेल उत्पादन फिर से बढ़ रहा था। विदेशी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अंतरराष्ट्रीय कर्ज देने वाले धीरे-धीरे बातचीत फिर से शुरू कर रहे थे, और एनर्जी से जुड़ी कंपनियां सालों तक दूर रहने के बाद देश में व्यापार के मौकों की तलाश कर रही थीं। जब वेनेजुएला उबरने की ओर बढ़ रहा था, तभी आपदा आ गई। 24 जून की शाम को, देश के उत्तरी तट पर एक मिनट से भी कम समय में दो जबरदस्त भूकंप आए। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था। ठीक 39 सेकंड बाद, 7.5 तीव्रता का और भी तेज भूकंप आया। इन भूकंपों ने युमारे के पास सैन सेबेस्टियन फॉल्ट सिस्टम को हिला दिया और काराकस, ला गुएरा, काराबोबो, मिरांडा, याराकुय और अरागुआ सहित कई बड़े इलाकों को झकझोर दिया। यह 1900 के बाद से वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और बचावकर्मी अभी भी गिरी हुई इमारतों में खोजबीन कर रहे हैं। लापता लोगों पर नजर रखने वाले स्वतंत्र संगठनों का मानना है कि वेनेजुएला में मीडिया पर लगी पाबंदियों के कारण लापता लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जो देश अभी-अभी उबरना शुरू ही हुआ था, उसके लिए यह समय बहुत ही बुरा साबित हुआ। भूकंप के ठीक तीन दिन बाद, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने रेपिडा सिस्टम का इस्तेमाल करके तबाही का आकलन करना शुरू किया। यह तकनीक सैटेलाइट इमेज, भूकंप मॉडल और आबादी के डेटा का इस्तेमाल करके नुकसान का अनुमान लगाती है, ताकि बचाव दल प्रभावित इलाकों तक पूरी तरह पहुंचने से पहले ही नुकसान का अंदाजा लगा सकें। इसका पहला अनुमान चौंकाने वाला था। भूकंप से लगभग 6.7 अरब डॉलर का सीधा फिजीकल नुकसान हुआ, और कुल नुकसान 4.7 अरब डॉलर से 8.7 अरब डॉलर के बीच होने की संभावना है। यह रकम अकेले वेनेजुएला के सालाना इकोनॉमिक प्रोडक्शन का लगभग 6 फीसदी है, जो एक मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया।

एचएएल कंपनी ने खोला खजाना, हर शेयर पर होगी 10 रुपये की एक्स्ट्रा कमाई

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत की दिग्गज सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने निवेशकों के बीच मुनाफा बांटने का फैसला किया है। सोमवार को कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। इससे पहले फरवरी के महीने में भी इसी कंपनी ने 35 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया था। अब डिविडेंड के इस प्रस्ताव को कंपनी की आगामी सालाना आम बैठक में रखा जाएगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलते ही निवेशकों के बैंक खातों में पैसे भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर आप इस डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, तो एक जरूरी तारीख आपको याद रखनी होगी। एजीएम में शेयरधारकों की मुहर लगने के बाद, इस लाभांश के भुगतान के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 14 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) तय की है। इसका मतलब यह है कि अगर इस तय तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में एचएएल के शेयर मौजूद रहते हैं, तो आप इस डिविडेंड को पाने के पूरी तरह से हकदार होंगे। कंपनी ने साफ तौर पर बताया है कि एजीएम में प्रस्ताव पास होने के ठीक 30 दिनों के भीतर सभी योग्य निवेशकों के बैंक खातों में लाभांश की यह रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। एचएएल अपने निवेशकों को निराश नहीं करती और समय-समय पर उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बांटती आई है। अगर पिछले कुछ सालों के वित्तीय रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो कंपनी का प्रदर्शन इस मोर्चे पर बेहतरीन रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी ने अपने निवेशकों को कुल 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था, जिस पर कंपनी ने करीब 1,671.94 करोड़ रुपये खर्च किए थे। वहीं, साल 2023-24 में 35 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 1,471.31 करोड़ रुपये निवेशकों में बांटे गए थे। 2022-23 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड 55 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था। इससे थोड़ा और पीछे जाएं तो 2021-22 में 50 रुपये, 2020-21 में 30रुपये तथा 2019-20 में 33 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को मिल चुका है।

भारतीय महिला टीम की 2028 ओलंपिक की सीट पक्की

पुरुष टीम को कब तक करना होगा इंतजार?

इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (आईओसी) ने 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी होगी, जहां महिला और पुरुष दोनों वर्गों में टी-20 फॉर्मेट में छह-छह टीमें गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगी। इसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया का प्रतिनिधित्व पक्का है। हर इवेंट में पांच क्वालिफिकेशन स्थान मौजूदा आईसीसी प्रतियोगिता और T20I रैंकिंग को मिलाकर तय की जाएंगे, जो मौजूदा अप्रूव्ड और पब्लिश्ड एफटीपी स्ट्रक्च SX के हिसाब से होंगे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के कॉम्पिटिशन में छठा और आखिरी स्थान नए आईसीसी ओलंपिक क्वालिफायर से तय होगा, जो 2027 में होगा।

भारतीय महिला टीम की सीट पक्की

भारत महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के जरिए क्वालीफाई कर लिया है। भातर के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों की सीट पक्की हुई है। भारत जारी महिला वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और अपने ग्रुप में तीसरे पायदान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत की पुरुष टीम को क्वालिफिकेशन पक्का करने के लिए दिसंबर 2026 तक इंतजार करना होगा। भारतीय पुरुष टीम को हाल ही में आयरलैंड के हाथों दो मैचों की टी-20 सीरीज में ऐतिहासिक हार मिली।

मुझे थिएटर में जाकर हर तरह की फिल्में देखना पसंद है

सेलिब्रिटी पर हमेशा ट्रेंड्स के साथ चलने का दबाव रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन पर ये दबाव इसलिए भी रहता है कि क्योंकि ब्यूटी ट्रेंड्स रातों-रात बदल जाते हैं। हालांकि अनन्या पांडे के लिए, आज खूबसूरती का मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी असलियत को अपनाना है।

ट्रेंड को फॉलो नहीं करतीं अनन्या

एक्ट्रेस ने बताया कि वह कभी भी ब्यूटी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागतीं, बल्कि वही चीजें अपनाती हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से पसंद आती हैं।

अपने लिए सही चीजें चुनती हैं अनन्या

'कॉल मी बे' की एक्ट्रेस ने कहा कि मैं ट्रेंड्स को फॉलो वालों में से नहीं हूं। मुझे असल में ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए क्या सही है।

अनन्या का काम

अनन्या को फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' और 'चांद मेरा दिल' जैसी हालिया फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली, हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाईं। सफलता और असफलता दोनों का अनुभव कर चुकीं यह एक्ट्रेस बड़े पर्दे के जादू में पक्का यकीन रखती हैं।

नई पीढ़ी से अपील : अनन्या पांडे कहती हैं मुझे लगता है कि सिनेमा हमेशा रहेगा। मुझे थिएटर में जाकर हर तरह की फिल्में देखना पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा मजा हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में देखने में आता है। मेरे लिए, फिल्में देखना मेरे बड़े होने का एक अहम हिस्सा रहा है। मैं नई पीढ़ी को थिएटर जाकर फिल्में देखने और हमारे सिनेमा को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगी।

जेनेलिया ने गंगा में लगाई डुबकी

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने 'वट पूर्णिमा' के त्योहार पर गंगा नदी में डुबकी लगाई। इस खास मौके पर उन्होंने अपने पति रितेश देशमुख को याद किया। साथ ही सोशल मीडिया पर इसका एक खूबसूरत वीडियो भी शेयर किया है।

जेनेलिया ने शेयर की खास झलक

जेनेलिया ने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'वट पूर्णिमा' के त्योहार के दिन गंगा में डुबकी लगाते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं। वीडियो को शेयर करते हुए जेनेलिया ने लिखा कि "Vat Purnima पर डुबकी लगाई और तुम्हें याद किया- मेरे पति रितेश।

जेनेलिया और रितेश की जोड़ी

जेनेलिया और रितेश बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक हैं। दोनों की मुलाकात साल 2000 के शुरुआत में उनकी पहली फिल्म 'तुझे मेरी कसम' की शूटिंग के दौरान हुई थी। लगभग 10 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने 3 फरवरी 2012 को महाराष्ट्रीयन और ईसाई रीति-रिवाजों से शादी कर ली। जेनेलिया और रितेश के दो बेटे हैं- रियान और राहिल। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने मजेदार और प्यारे पारिवारिक वीडियो शेयर करते रहते हैं। जेनेलिया और रितेश को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म 'राजा शिवाजी' में एक साथ देखा गया था।

क्या है 'वट पूर्णिमा'?

वट पूर्णिमा शादीशुदा महिलाओं का एक मुख्य हिंदू त्योहार है, जिसे खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कहानी से प्रेरणा लेकर अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं इस दिन बरगद (वट) के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं।

राजामौली को पेरिस में मिला सम्मान

एस.एस. राजामौली को पेरिस के 'सिनेमाथेक फ्रैंकेस' में स्थायी जगह देकर सम्मानित किया गया है। यह फिल्ममेकर और भारतीय सिनेमा के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। 93 साल के ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर कोस्टा-गवरस के उनकी फिल्में देखने के लिए आठ घंटे तक वहां रुकने से राजामौली का दिन बन गया। राजामौली की फिल्में जिनमें आरआरआर और बाहुबली फ्रेंचाइजी शामिल हैं, दुनिया भर में पसंद की गई हैं। उन्हें दुनिया के सबसे सम्मानित फिल्म संस्थानों में से एक ने एक खास कार्यक्रम में सम्मानित किया, जिसमें उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग और उसके बाद एक मास्टरक्लास आयोजित की गई थी।

राजामौली की फिल्मों के लिए आठ घंटे बैठे रहे कोस्टा-गवरस

इस इवेंट पर तब और ज्यादा ध्यान गया जब कोस्टा-गवरस ने इतनी उम्र में भी राजामौली की फिल्में देखने और उनकी मास्टरक्लास में शामिल होने के लिए लगभग आठ घंटे बिताए। जिस मुलाकात के छोटा होने की उम्मीद थी, वह राजामौली के काम के साथ पूरे दिन के कार्यक्रम में बदल गई, जिससे भारतीय फिल्म निर्माता और उनके परिवार ने गर्मजोशी से प्रतिक्रिया दी। राजामौली को यह सम्मान 'सिनेमाथेक फ्रेंकाइस' में दिया गया। यह इवेंट आर्काइव 1936 में हेनरी लैंगलोइस ने शुरू किया था और यह लंबे समय से दुनिया भर के बड़े फिल्म निर्माताओं का सम्मान करता आ रहा है। इस मौके पर भारतीय सिनेमा की दुनिया भर में बढ़ती लोकप्रियता का जश्न मनाने के लिए एक खास रेट्रोस्पेक्टिव के तहत आरआरआर (2022), ईगा (2012) और बाहुबली : द बिगिनिंग (2015) की स्क्रीनिंग की गई। इस इवेंट को 'इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न' और विदेश मंत्रालय का सहयोग मिला।

राजामौली ने जताया आभार

राजामौली ने इस सम्मान को लेकर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि पेरिस में मेरा होना और मेरी फिल्मों की स्क्रीनिंग होना ही मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन एक सुखद सरप्राइज ऐसा था जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। यह एक ऐसी भावना है जिसे मैं पूरी तरह से शब्दों में बयां नहीं कर सकता। महान हेनरी लैंगलोइस के नाम पर बने दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म संस्थानों में से एक के हॉल में स्थायी जगह मिलना, एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा।

वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में फिट करने का वक्त आ गया है

प्रतिभाशाली वैभव सूर्यवंशी के लिए एक मजबूत टीम में कैसे जगह बनाई जाए, यह भारतीय टीम के ब्रिटेन दौरे से पहले सबसे बड़ा सवाल था और अब आयरलैंड से दो मैच में अप्रत्याशित हार के बाद लगता है कि टीम प्रबंधन को इसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि 15 वर्षीय सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण का मौका मिल जाएगा, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करने पर अडिग रहा जिसमें पहले से आजमाए गए खिलाड़ियों को पर्याप्त मौका देना शामिल है, लेकिन अब लगता है कि इस प्रक्रिया की समीक्षा करने का समय आ गया है।

सैमसन और अभिषेक ओपनिंग के हकदार थे

संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने टी-20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था और इसलिए वह इस श्रृंखला में खेलने के हकदार थे। यही वजह थी कि सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली, लेकिन अब लगता है कि सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में जगह देनी ही होगी। ऐसा तभी नहीं होगा जबकि मुख्य कोच गौतम गंभीर की अगुवाई वाले टीम प्रबंधन को यह लगता हो कि सैमसन और अभिषेक की जोड़ी का कोई सानी नहीं है। चयन प्रक्रिया उतनी सरल नहीं होती जितनी दिखती है, लेकिन भारतीय टीम के रणनीतिकारों को एक जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की टी-20 श्रृंखला के लिए उपयुक्त समाधान ढूंढना होगा। पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो इंग्लैंड की पिचें थोड़ी सपाट रहने की संभावना है।

■ अगर टीम प्रबंधन सैमसन-अभिषेक की जोड़ी को नहीं बदलना चाहता, तो ईशान किशन समेत बाकी बल्लेबाजों को एक स्थान नीचे आना होगा। इस नए क्रम में सूर्यवंशी तीसरे, किशन चौथे, श्रेयस अय्यर पांचवें, तिलक वर्मा छठे, शिवम दुबे सातवें और अक्षर पटेल आठवें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सूर्यांश शेडगे को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जगह नहीं मिलेगी। अगर शिवम दुबे सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो उनसे चार ओवर गेंदबाजी करने की उम्मीद की जाएगी क्योंकि शीर्ष क्रम में केवल अभिषेक ही कामचलाऊ स्पिनर हैं। दुबे का स्तर हार्दिक पंड्या जैसा नहीं हैं और टी20 टीम में वह ज्यादा से ज्यादा छठे गेंदबाज ही हो सकते हैं। असली समस्या यहीं से शुरू होती है।

■ पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने आज तक से कहा कि वैभव सूर्यवंशी जिस तरह की फॉर्म में हैं, उसे देखते हुए उन्हें आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में अंतिम एकादश में जगह मिलनी चाहिए थी। अभिषेक और सैमसन को एक-एक मैच में मौका दिया जा सकता था और सूर्यवंशी को दोनों मैचों में मौका दिया जा सकता था। इस प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी को आजमाने के लिए यह एक अच्छा मंच था। उन्होंने कहा कि सूर्यवंशी को इंग्लैंड में पहले मैच से ही खिलाना होगा। टीम प्रबंधन को खराब फॉर्म वाले बल्लेबाजों को बाहर करके सूर्यवंशी को मौका देना चाहिए। भले ही आप अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को टीम में बनाए रखते हुए उन्हें तीसरे नंबर पर उतारें लेकिन सूर्यवंशी को एक जुलाई को इंग्लैंड में होने वाले पहले मैच में खेलना ही होगा। अगर आप पहले मैच में इंग्लैंड पर जीत दर्ज करना चाहते हैं तो सूर्यवंशी को खेलना ही होगा।

■ भारत के सभी टी-20 बल्लेबाजों को आईपीएल में बड़े शॉट लगाना पसंद है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक विकल्प मौजूद है। ऐसी स्थिति में जब वह मुश्किल पिच पर खेलते हैं तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। भारत जब इस तरह के मुश्किल विकेट पर खेलता है और वह आक्रामक रवैया बनाए रखकर अपने 'प्लान बी' को नजरअंदाज करता है तो उसके बल्लेबाज अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अगर सैमसन और अभिषेक की सलामी जोड़ी बरकरार रखकर सूर्यवंशी को टीम में रखा जाता है और पांच विशेषज्ञ गेंदबाजों को भी बरकरार रखा जाता है तो ऐसे में किशन और तिलक वर्मा में से किसी को बाहर करना होगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सबसे तार्किक समाधान सैमसन को टीम से बाहर करना होगा। वह आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैच में नहीं चल पाए थे। गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में वह लय में नजर नहीं आए। अगर टीम प्रबंधन को गेंदबाजी में संतुलन बनाए रखना है तो उसे सैमसन से बात करनी होगी।

संजय दत्त इंडस्ट्री के माचो मैन हैं: उर्मिला मातोंडकर

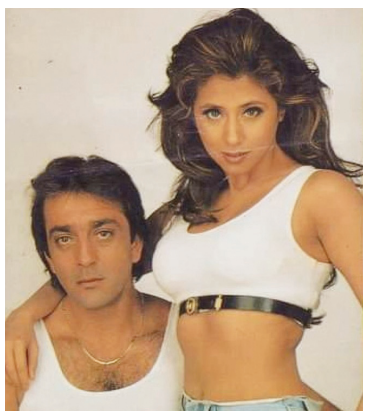

उर्मिला मातोंडकर ने डांस के मामले में बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और उनके मूड के बारे में कुछ अनसुने तथ्यों का खुलासा किया। डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5 में बतौर गेस्ट पहुंचीं उर्मिला मातोंडकर ने दर्शकों को संजय दत्त के साथ अपने अनुभवों से कुछ अनकही कहानियों और यादों को साझा किया।

डांस का जिक्र होते ही संजय दत्त का मूड ऑफ हो जाता था

शो के दौरान जब होस्ट हर्ष लिंबाचिया ने संजय दत्त के साथ काम करने के बारे में पूछा तो उर्मिला मातोंडकर ने पर्दे के पीछे की एक मजेदार याद साझा की। उन्होंने कहा कि संजू की एक बात मैं आपको बताती हूं, मैंने उनके साथ दो-तीन फिल्में की हैं। सभी अभिनेत्रियां आपको बताएंगी जिन्होंने उनके साथ काम किया है। जब भी डांस का गाना आता है, वो इतने खराब मूड में रहते हैं और कहते हैं कि यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। फिर चुपके से जाकर रिहर्सल करके फाइनल में जब वो आकर डांस करते, तो आपको लगता है, तो इतना क्या बोल रहे थे? उनका स्वभाव ही ऐसा है। वह बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं क्योंकि वह इंडस्ट्री के असली 'माचो मैन' हैं, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है।

ओटीटी पर आएगा फैमिली मैन का चौथा सीजन

ओटीटी की दुनिया की सबसे चर्चित वेब सीरीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी स्टारर सीरीज द फैमिली मैन का नाम जरूर शामिल होगा। अब तक इस सीरीज के तीन सीजन को रिलीज किया जाए चुका है और तीनों की सफल साबित हुई हैं। अब द फैमिली मैन के क्रिएटर राज निदिमोरु ने इसके चौथे सीजन की पुष्टि कर दी है और बताया है कि स्पाई थ्रिलर सीरीज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

ओटीटी पर कहां आएगी द फैमिली मैन 4?

बात की जाए द फैमिली मैन 4 की ओटीटी रिलीज की तो ये सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो का पॉपुलर शो है। इस आधार पर आपको ये प्राइम वीडियो पर ही देखने को मिलेगी। हालांकि, अभी चौथे सीजन की रिलीज डेट में काफी साल लगने वाले हैं।

द फैमिली मैन 4 पर लगी मुहर

राज एंड डीके की जोड़ी ने साल 2019 में द फैमिली मैन वेब सीरीज की शुरुआत की, जिसमें मनोज बाजपेयी ने भारतीय खुफिया जांच एजेंसी के एजेंट श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है, जो अपने काम के साथ-साथ परिवार की जिम्मेदारी को भी बखूबी संभालता है। बीते साल आए द फैमिली मैन 3 को रिलीज किया गया था और उस वक्त लगा कि अब ये सीरीज का एंड है। लेकिन हाल ही में राज निदिमोरु ने वैराइटी इंडिया को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में द फैमिली मैन के चौथे सीजन पर मुहर लगाई है और बताया है कि हमने द फैमिली मैन के सीजन 3 और 4 को एक लंबी कहानी के तौर पर प्लान किया था। कुछ दर्शकों को लगा कि तीसरा सीजन बीच में ही खत्म हो गया, लेकिन हमारे हिसाब से मुख्य कहानी एक तार्किक मोड़ पर पहुंच गई थी। सिर्फ श्रीकांत तिवारी का सफर अधूरा रह गया था क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से अगले सीजन में जारी रहने वाला था। इस आधार पर हम द फैमिली मैन के चौथे सीजन की स्क्रिप्ट को तेजी से लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सीरीज की कहानी को दूसरे हिस्से तक पहुंचना है। इस तरह से राज निदिमोरु द्वारा मनोज बाजपेयी स्टारर द फैमिली मैन सीजन 4 का आधिकारिक पुष्टिकरण किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट हाई हो गई है।

'आवारापन 2' का टीजर हुआ रिलीज

विशेष फिल्म्स ने आधिकारिक तौर पर 'आवारापन 2' का टीजर रिलीज कर दिया है। 2007 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' के 19 साल के लंबे समय बाद आखिरकार इसका सीक्वल आ रहा है। इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पाटनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'?

विशेष फिल्म्स ने आज आधिकारिक तौर पर 'आवारापन 2' के टीजर को रिलीज करके इमरान हाशमी के प्रशंसकों को खुश कर दिया है। 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जो स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर पड़ रहा है।

निमार्ताओं ने जारी किया टीजर

आज विशेष फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर आगामी फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर साझा किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि 19 साल के लंबे इंतजार के बाद 'आवारापन 2' अब खत्म हुआ। शिवम वापस आ गया है। इस फिल्म में इमरान हाशमी शिवम के किरादार में नजर आएंगे।

क्या है टीजर में खास

इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के टीजर की शुरुआत इन लाइन से शुरू होती है कि कछ लोगों की कहानिंया उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती है, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है। इसी के साथ फिल्म में इमरान को एक्शन करते दिखाया गया है। इसके साथ ही शबाना आजमी और दिशा पाटनी की खास झलक भी दिखाई गई है।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित।
दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक :** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com** RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 **स्थानीय संपादक :** शिवप्रताप